



पेपर लीक: अब फास्ट ट्रेक कोर्ट में होगी सुनवाई

नकल विरोधी कानून कसेगा आरोपियों पर नकेल

नई दिल्ली। नीट परीक्षा के पर्चे लीक होने की घटना के बाद से देशभर में जारी छात्र आंदोलन और आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने युवाओं के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष फास्ट-ट्रेक अदालतों का गठन किया जाएगा, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में खड़ा कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।

इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म %इं% पर एक संदेश साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के युवाओं का सुनहरा भविष्य और उनके हितों की सुरक्षा वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में



अनुचित साधनों के इस्तेमाल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने और मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट-ट्रेक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। इस दिशा में संबंधित

मंत्रालयों और विभागों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में यह एक बेहद निर्णायक मोड़ साबित होगा। युवाओं के करियर और मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी आपराधिक तत्व को किसी भी

कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

यसरकार के इस फैसले के बाद अब राज्यों और केंद्र स्तर पर विशेष फास्ट-ट्रेक अदालतों की स्थापना की जाएगी। इससे पेपर लीक से जुड़े मुकदमों की सुनवाई सालों-साल लटकने के बजाय तय समय-सीमा के भीतर पूरी हो सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से परीक्षा प्रणाली में धांधली करने वाले गिरोहों में कानून का खौफ भी पैदा होगा।

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर काँकरोच जनता पार्टी% के प्रदर्शन का व्यापक असर आम जनजीवन और सार्वजनिक परिवहन पर पड़ा है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लगातार दूसरे दिन, यानी गुरुवार को भी दिल्ली मेट्रो के 16 प्रमुख स्टेशनों को यात्रियों के लिए पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया है।

युवाओं का उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की प्राथमिकता: शाह

नई दिल्ली। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम मोदी के इस एलान का केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने समर्थन दिया है। मित शाह ने सोशल मीडिया जरिए कहा कि युवाओं का हित मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पीएम के फास्ट ट्रेक कोर्ट के फैसले को मील का पत्थर बताया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रेक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में पेपर लीक पर कार्रवाई की बात कही थी। उन्होंने बैठक में कहा कि पेपर लीक की खबर मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भजा गया। उन्होंने कहा कि आगे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, चौथे दिन भी कार्यवाही ठप

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सभी गतिरोध बना रहा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के लगातार हंगामे के चलते कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी, जिससे बिना किसी कामकाज के सदन दिन भर के लिए स्थगित हो गए। सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से बचने और पूर्व शर्तें थोपने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भी मुखर रहा। गुरुवार को मौनसून सत्र के चौथे दिन, संसद के दोनों सदनों में हृदयशुद्ध

पेपर %लीक% मामले पर चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग फिर से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

हमारे घर या दफ्तर आइए, पेपर लीक पर बात करेंगे



केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने छात्र प्रदर्शनकारियों को अपने घर या कार्यालय में बातचीत के लिए आमंत्रित किया, यह संकेत देते हुए कि सरकार छात्रों के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी सरकार की ओर से बार औपचारिक प्रस्ताव भेजने की पुष्टि करते हुए बातचीत के लिए अपनी उपलब्धता दोहराई, जिससे पेपर लीक मामले में समाधान की उम्मीद जगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए तैयार है और उन्हें अपने घर या सरकारी दफ्तर में मिलने के लिए बुलाया।

आतंकवाद जारी रहने तक निलंबित रहेगी सिंधु जल संधि

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में पाकिस्तान की टिप्पणियों पर कड़ा जवाब दिया है और साफ शब्दों में दो टुक कहा कि कि सीमा पार से आतंकवाद जारी रहने तक सिंधु जल संधि निलंबित रहेगी।

भारत ने कहा कि जब सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल सरकारी नीति के हथियार के रूप में किया जाता है तो सिंधु जल संधि के तहत सहयोग की उम्मीद नहीं जा सकती।

भारत ने यह भी दोहराया कि जम्मू-कश्मीर देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हमेशा था, है और रहेगा। बता दें कि गत वर्ष 22 अप्रैल



को पहलगाय आतंकी हमले के बाद भारत ने इस सिंधि को निलंबित कर दिया था।

यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्राकृतिक संसाधनों का प्रशासन शांति, सुरक्षा और समृद्धि की नींव विषय पर हुई

उच्चस्तरीय खुली बहस के दौरान यह बात कही।

पर्वतनेनी ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने गलत नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा का दुरुपयोग किया, जिसके कारण भारत को जवाब देना पड़ा।

उन्होंने कहा, सिंधु जल संधि को लेकर हमारा रुख एकदम स्पष्ट है। जब सीमा पार आतंकवाद का सरकारी नीति के हथियार के तौर पर नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो आपसी विश्वास व सद्भाव के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।

सोशल मीडिया की लोकप्रियता सफलता का पैमाना नहीं: सीजेआई

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कानूनी पेशे से जुड़े युवाओं को सोशल मीडिया और ऑनलाइन विजिबिलिटी को लेकर महत्वपूर्ण सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली लोकप्रियता या ध्यान आकर्षित करने को किसी वकील को अपनी वास्तविक सफलता नहीं माननी चाहिए। कानूनी पेशे में असली सम्मान, स्थायी पहचान और सफलता कोर्ट रूम के भीतर की गई कड़ी मेहनत, लगन और बनाई गई क्रेडिटबिलिटी (विश्वसनीयता) से मिलती है, न कि किसी डिजिटल मंच या ऑनलाइन टीआरपी से। सीजेआई सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) द्वारा 2025 बैच के नए एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) वकीलों के सम्मान में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चित होना और ध्यान खींचना बेहद आसान है।



रायपुर। अमलीपदर की ऐतिहासिक रथयात्रा छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। भगवान श्री जगन्नाथ सबको साथ लेकर चलने और लोककल्याण का संदेश देते हैं। महाप्रभु का आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर सदैव बना रहे, यही उनकी प्रार्थना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज गरियाबंद जिले के अमलीपदर में आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथयात्रा महापर्व को संबोधित करते हुए यह बात कही। **विस्तृत समाचार पेज-8 पर**

छात्रों का भविष्य खतरे में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

नई दिल्ली। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा कि सरकार देश के युवाओं की उम्मीदों और उनके भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग मेहनती छात्रों का भविष्य खतरे में डालेंगे, उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है और अब भी कहते हैं कि वह हर मामले की जांच कराने के लिए तैयार हैं। वह फास्ट-ट्रेक कोर्ट लाएंगे ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। देश और दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी के संकल्प का मतलब उसे पूरा करना होता है। एक्स पर एक पोस्ट में, नवीन ने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारी सरकार हमारे युवाओं की आकांक्षाओं, कड़ी मेहनत और भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने परीक्षा के पेपर लीक जैसे अपराधों में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रेक कोर्ट बनाने की भी घोषणा की।

सरकार-प्रदर्शनकारी मिलकर निकालें समाधान : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने गुरुवार को केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे नीट पेपर लीक में गड़बड़ियों को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे काँकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन का शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें। एक्स पर एक पोस्ट में मायावती ने कहा कि संसद के पास चल रहे अनिश्चितकालीन विरोध-प्रदर्शन ने छात्रों और उनके परिवारों पर पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं के गंभीर असर को उजागर किया है। मायावती ने लिखा कि राष्ट्रीय राजधानी में संसद के पास जंतर-मंतर पर काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में कई दिनों से अनिश्चितकालीन विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। यह प्रदर्शन नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं के कारण छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले गंभीर असर को उजागर कर रहा है। मायावती ने कहा कि इस विरोध-प्रदर्शन ने सड़कों से लेकर संसद तक भारी हंगामा खड़ा कर दिया है।

कांग्रेस और सपा छात्रों को कर रहे बदनाम : सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे नीट विरोध-प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में संसद सत्र को घेरकर अशांति फैलाने और छात्रों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया और विस्थापित किया गया, तो विपक्षी दल चुप रहे; लेकिन जब नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदुओं की सुरक्षा और बचाव पर जोर दिया, तो उन्होंने एक नकारात्मक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में संसद सत्र के दौरान हंगामा किया, माहौल खराब किया और अशांति फैलाकर छात्रों को बदनाम करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि न केवल दिल्ली में, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में भी हालात बिगाड़ने की कोशिशें की गईं। कांग्रेस सरकार के समय, जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की निशाना बनाया गया और उन्हें विस्थापित किया गया।

पीएम मोदी के फास्ट-ट्रेक कोर्ट पर केजरीवाल का हमला

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पेपर लीक मामले के लिए फास्ट-ट्रेक कोर्ट बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों की चिंताएं दूर नहीं होंगी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा कि गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री ने घोषणा की- पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रेक कोर्ट बनाए जाएंगे। धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे का क्या हुआ? मोदी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का बयान किसी ऐसे व्यक्ति जैसा लगता है जो हार चुका हो, दिशाहीन हो, लेकिन अहंकारी भी हो। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की घोषणा की आलोचना करते हुए कहा कि यह छात्रों की मांग के मुकाबले नाकामोई है और केंद्र सरकार पर उन्हें गुमराह करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत में रैप और पास्को जैसे मामलों के लिए पहले से ही फास्ट-ट्रेक कोर्ट हैं। लेकिन इनमें से कई कोर्ट या तो सुनवाई नहीं कर पाते या फिर सामान्य कोर्ट से ज्यादा समय लेते हैं।

छात्रों के समर्थन में 26 को मुंबई में मोर्चा खोलेंगे ठाकरे बंधु

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को मुंबई में 26 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले संभावित असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी। एमएनएस प्रमुख ने कहा कि जो कोई भी रविवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने की कोशिश करेगा, उसकी पिटाई की जाएगी।

राज ठाकरे का यह बयान तब आया है जब एमएनएस और शिवसेना (यूबीटी) ने छात्रों के समर्थन में एक संयुक्त विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है। पिछले कुछ दिनों में, मुंबई में जंतर-मंतर आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। राज और उद्धव ठाकरे का काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अधिजीत दिपके को अपना समर्थन दिया है, जो इस समय दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूबीटी प्रमुख ने दिल्ली का दौरा भी किया और अपना समर्थन जताने के लिए जंतर-मंतर पर सीजेपी और विरोध प्रदर्शन कर रहे अन्य युवाओं से मुलाकात की। ठाकरे परिवार के अलावा, एनसीपी के शरद पवार जैसे कई अन्य नेताओं ने भी इन विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया है।

वंदे मातरम विधेयक 2026: राष्ट्रीय सम्मान या अनिवार्य देशभक्ति

किशन सनमुखदास भावनानी

वंदे मातरम विधेयक 2026- भारतीय बहुलतावादी लोकतंत्र में चुनौती- राष्ट्रीय गौरव की रक्षा भी हो, संविधान की आत्मा भी सुरक्षित रहे और नागरिक की अंतरात्मा की स्वतंत्रता भी अक्षुण्ण बनी रहे।

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 केवल एक दंडात्मक कानून का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों राष्ट्रीय सम्मान, संवैधानिक स्वतंत्रता और नागरिक कर्तव्य के बीच संतुलन स्थापित करने की परीक्षा भी है।

वैश्विक स्तर पर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में जुलाई 2026 का मौसून सत्र केवल राजनीतिक टकराव के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय

प्रतीकों की संवैधानिक स्थिति को लेकर शुरू हुई एक नई बहस के कारण भी लंबे समय तक याद किया जा सकता है। 20 जुलाई 2026 को जब यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, उसी समय विपक्ष ने इसके विरोध में तीखी आपत्ति दर्ज कराई। विभिन्न विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक बताते हुए अन्य तात्कालिक मुद्दों पर चर्चा की मांग की। इसद में लगातार हंगामा होता रहा और विधेयक पर विस्तृत चर्चा प्रारंभ नहीं हो सकी। 21 जुलाई 2026 तक की संसदीय स्थिति के अनुसार यह विधेयक प्रस्तुत तो हो चुका था, किंतु उस पर विस्तार-विमर्श और आगे की विधायी प्रक्रिया गतिरोध के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। अर्थात् विधेयक अभी कानून नहीं बना है और उसे संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की

स्वीकृति प्राप्त करना शेष है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 ने संसद से लेकर न्यायपालिका, संविधान विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक व्यापक चर्चा को जन्म दिया। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि प्रस्तावित संशोधन का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय वंदे मातरम को वही वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है जो अब तक राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान जन गण मन को प्राप्त है। यदि यह विधेयक वर्तमान स्वरूप में कानून बनता है तो किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करना, उसके गायन



में बाधा डालना अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम में उसका अनादर करना तीन वर्ष तक के कारावास जुर्माने या दोनों से दंडनीय अपराध बन सकता है। यहीं से वह संवैधानिक प्रश्न प्रारंभ होता है जिसने पूरे देश में चर्चा को जन्म दिया है, क्या यह राष्ट्रीय सम्मान को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है? या फिर यह देशभक्ति को कानून के माध्यम से अनिवार्य बनाने का प्रयास माना जाएगा?

साथियों, मीडिया में आई जानकारी

के अनुसार सरकार का पक्ष अत्यंत स्पष्ट है। केंद्र का कहना है कि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए विरुद्ध संघर्ष के दौरान लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी गीत को प्रेरणा का स्रोत बनाया। अनेक कांतिकारी फांसी के फंदे पर चढ़ते समय वंदे मातरम का उद्धोष करते थे। संविधान सभा के अंतिम चरण में 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया था कि जन गण मन राष्ट्रगान होगा जबकि वंदे मातरम को समान सम्मान प्राप्त रहेगा। सरकार का तर्क है कि स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए अब समय आ गया है कि

इसे भी वैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति जानबूझकर इसका अपमान न कर सके। सरकार यह भी कह रही है कि यह बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि सटीकता से राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए लाया गया है।

साथियों, यह विधेयक वास्तव में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 में संशोधन का प्रस्ताव है। वर्तमान अधिनियम मुख्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान को दंडनीय बनाता है। प्रस्तावित संशोधन के बाद पहली बार राष्ट्रीय वंदे मातरम को भी इसी श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है, उसके

गायन में व्यवधान उत्पन्न करता है, किसी सार्वजनिक समारोह में उसे रोकने का प्रयास करता है या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधि करता है, तो उस के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि यह संशोधन केवल जानबूझकर किए गए अपमान पर लागू होगा, यह सटीकता से सामान्य परिस्थितियों अथवा व्यक्तिगत विवेक पर नहीं।

साथियों, लेकिन यही वह बिंदु है जहां से संवैधानिक विवाद प्रारंभ होता है। विपक्ष का कहना है कि संविधान सभा ने जानबूझकर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के बीच कानूनी अंतर बनाए रखा था। यदि संविधान निर्माताओं की मंशा दोनों को समान कानूनी दर्जा देने की होती तो संविधान में उसी समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाता।

पेपर लीक माफिया देश में सक्रिय, कांग्रेस सड़क से सदन की लड़ेगी लड़ाई: उमेश पटेल

पूर्व मंत्री ने कहा कि परीक्षा में पार्दर्शिता नहीं है, नीट एग्जाम को लेकर लोगों के मन में भरोसा होना चाहिए

गौरेला पेंड्रा मरवाही। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रही है। इसी कड़ी में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे पर पहुंचे। पेंड्रा में उन्होंने छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया।

उमेश पटेल ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक देश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की कई घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य माफियाओं की तरह अब पेपर लीक माफिया भी पूरे देश में सक्रिय हो चुका है। सीबीआई ने खुद कहा कि 20



से 30 लाख में पेपर बेचे गए। परीक्षा में पार्दर्शिता नहीं है, नीट एग्जाम को लेकर लोगों के मन में भरोसा होना चाहिए, वो भी नहीं है। भाजपा सरकार इस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा खामियाजा देश के लाखों मेहनती छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों के मन में जो विश्वास होना चाहिए था, वह लगातार कमजोर हुआ है। मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग रहा है, जबकि सरकार

दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में गंभीर नजर नहीं आती। पूर्व मंत्री ने कहा कि सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के खिलाफ भी आवाज उठाने पर छात्र को पाकिस्तानी बताने का आरोप लगाया। उमेश पटेल ने कहा कि यहां कोई भी प्रश्न उठाने पर देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। सिस्टम के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है। पटेल ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाएगी। उमेश पटेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे विरोध कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के घेराव के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न राज्यों में कांग्रेस कार्यालयों पर किए गए कथित पथराव और हमले उनकी हाताशा को दर्शाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है,

लेकिन कांग्रेस युवाओं की आवाज बनकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इधर बिलासपुर में भी जिला कांग्रेस कमेटी भी प्रकाश का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाएगी। उमेश पटेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे विरोध कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के घेराव के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न राज्यों में कांग्रेस कार्यालयों पर किए गए कथित पथराव और हमले उनकी हाताशा को दर्शाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है,

अवैध भण्डारण व पैकेजिंग यूनिट पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, गोदाम किया सील

बालोद। डोंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम बीजाभाटा स्थित मेसर्स मारुति एग्रो बायोटेक के गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से कृषि आदान सामग्री के भंडारण एवं पैकेजिंग का कार्य पाया गया। निरीक्षण दल ने गोदाम से भारी मात्रा में सामग्री जब्त कर उसे सील कर दिया है।

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार एवं कृषि विभाग के उप संचालक आशीष चन्द्राकर के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय निरीक्षण दल ने 21 जुलाई को मेसर्स मारुति एग्रो बायोटेक, प्रोप्राइटर भारती चन्द्राकर के गोदाम में दबिश दी थी। आशीष चन्द्राकर ने बताया कि मेसर्स मारुति एग्रो बायोटेक के गोदाम में अवैध रूप से पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा था।

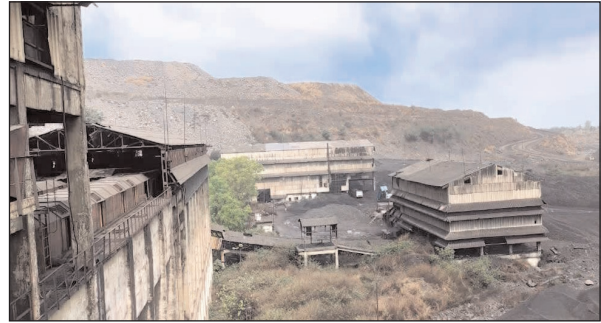
गोदाम में 10 किलोग्राम पैकिंग बाल्टी, 1305 भू लक्ष्मी, महासार जैव उर्वरक 500 मि ली। पैकिंग 2880 नग,



वीएजीएमआई प्रोम 08 किलोग्राम पैकिंग, 5129 बोरी (40 किलोग्राम), 153 बोरी (08 किलोग्राम) खुला पाया गया। साथ ही 1880 बोरी (50 किग्रा। पैकिंग) कच्चा माल कृषि सामग्री पाया गया। इसके अलावा पैकिंग मशीन-07 नग, तोलक-11 नग, बोरी सिलाई मशीन 03 नग पाया गया उन्होंने बताया कि निरीक्षण दल द्वारा उक्त कृषि सामग्रियों का नमूना लेकर गुणवत्ता जांच हेतु

प्रयोगशाला को प्रेषित करने की कार्रवाई की जा रही है। गोदाम परिसर में मारुति एग्रो बायोटेक संचालक प्रतिनिधि नीतीश चन्द्राकर, अगेश्वर चन्द्राकर ग्राम अण्डा उपस्थित रहे। उन्होंने कृषकों से अपील की है कि खाद, बीज, कीटनाशक अधिकृत एवं लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खरीदे और बिल अवश्य लें। किसी भी गैर लाइसेंसधारी या घूमंतू लोगों के संपर्क में न पड़े।

वन विभाग का सर्वे: 5 किमी दायरे में 2 कोल वाशरी



बिलासपुर। आसपास संचालित औद्योगिक गतिविधियों का प्रकृति पर क्या असर होता है, इसे छत्तीसगढ़ के कोपरा रामसर के बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। वन विभाग के प्राथमिक सर्वे में काले पानी का दंश झेल रहे कोपरा रामसर के 5 किलोमीटर के दायरे में दो कोल वाशरी और नी कोल डिपो का उल्लेख किया गया है। यह रिपोर्ट जिला वेटलैंड समिति के माध्यम से राज्य सरकार को भेज दी गई है। अब दिल्ली और राज्य की संयुक्त टीम विस्तृत सर्वे कर मास्टर प्लान तैयार करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे संरक्षण

और अन्य जरूरी कदमों पर निर्णय लिया जाएगा। करीब 210 हेक्टेयर (2.10 वर्ग किलोमीटर) में फैले कोपरा जलाशय को 7 महीने पहले रामसर का दर्जा मिला था। इसके बाद वन विभाग ने कैचमेंट क्षेत्र और आसपास की गतिविधियों का प्राथमिक सर्वे कराया। रिपोर्ट में कोपरा, बेलमंडी, सेटा और संबलपुर डूब बहतराई क्षेत्र में संचालित कोल वाशरी, कोल डिपो और अन्य गतिविधियों का विवरण शामिल किया गया है। विभाग के अनुसार ये क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित हैं, और बारिश का बहाव यहीं से जलाशय के कैचमेंट की ओर आता है।

दुर्ग में 22 दिनों से अतिथि शिक्षकों का आंदोलन

दुर्ग। पिछले 22 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच धरने पर देर रात पुलिस ने कार्रवाई की। हिंदी भवन के सामने चल रहे धरना स्थल से टेंट हटाकर जब्त कर लिया गया, साथ ही गुरुवार सुबह धरने पर पहुंचे करीब 50 अतिथि शिक्षकों को पुलिस बसों में बैठाकर वहां से ले गई। धरना स्थल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके बावजूद अतिथि शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

दुर्ग के हिंदी भवन के सामने बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ अतिथि शिक्षक पिछले 22 दिनों से संविलियन, सेवा सुरक्षा, समान कार्य के बदले समान वेतन और मानदेय बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। बुधवार को पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बड़ी संख्या में जवानों के साथ धरना स्थल पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें शाम तक धरना समाप्त करने की चेतावनी दी गई थी। चेतावनी के बावजूद शिक्षक डटे

बारिश और पुलिस सख्ती के बीच भी मांगों पर अड़े



रहे, जिसके बाद देर रात पुलिस ने टेंट उखाड़कर जब्त कर लिया और धरना स्थल खाली करा दिया। गुरुवार सुबह जब शिक्षक दोबारा धरना देने पहुंचे तो पुलिस ने करीब 50 प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर वहां से रवाना कर दिया। किसी भी नए प्रदर्शनकारी को धरना स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी को लेकर धरने पर बैठे थे। पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और धरना स्थल पर पुलिस बल तैनात रहा। अतिथि शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार के साथ अब तक केवल चर्चा हुई है, लेकिन उनकी किसी

अतिथि शिक्षक बोले- 20 हजार वेतन वो भी 10 महीने, कैसे होगा गुजारा, संविलियन और समान कार्य के बदले समान वेतन जैसी कई मांग

भी मांग पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक दूर-दराज और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन आज भी उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उनका आरोप है कि हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, समाधान नहीं। इससे पहले अतिथि शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा

मंत्री गजेंद्र यादव के दुर्ग स्थित निवास का लगभग 24 घंटे तक घेराव भी किया था। मंत्री से चर्चा के आश्वासन के बाद वे वापस धरना स्थल लौटे थे, लेकिन मांगों पर कोई फैसला नहीं होने से आंदोलन जारी रहा। अब पुलिस कार्रवाई के बाद भी शिक्षकों का कहना है कि टेंट हटाने या उन्हें हटाने से आंदोलन नहीं रुकेगा। जब तक सरकार लिखित और ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल सरकार और अतिथि शिक्षक संघ के बीच बातचीत की संभावना बनी हुई है, लेकिन अब तक किसी भी मांग पर सहमति नहीं बन सकी है।

शिक्षक की पिटाई से छात्र के सिर पर आई चोट, केस दर्ज



बालोद। बालोद जिले में मिडिल स्कूल के 12 वर्षीय छात्र को सॉर्ट रिसेस के बाद 1 मिनट लेट आना उस वक्त महंगा पड़ गया, जब शिक्षक ने गाली-गलौज कर उसकी पिटाई कर दी। इस घटना में छात्र के सिर में चोट आई है, जिसके चलते उसका अस्पताल में इलाज कराया गया और शिक्षक के खिलाफ डोंडीलोहारा थाना में मामला दर्ज किया गया।

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला डोंडीलोहारा थाना क्षेत्र के एक मिडिल स्कूल का है। परिजनों की शिकायत के अनुसार, मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक लोकेश्वर निषाद ने कक्षा 7वीं के 12 वर्षीय छात्र के साथ गाली-गलौज और मारपीट की है।

बताया जा रहा है कि सॉर्ट रिसेस के दौरान छात्र क्लास रूम में 1 मिनट की देरी से पहुंचा, जिसके बाद शिक्षक ने उसके साथ गाली-गलौज की और उसको बेरहमी से पिट दिया। इस पिटाई में छात्र के सिर पर चोट आई, जिसके चलते उसे आनन फानन में डोंडीलोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और इलाज कराया गया। घटना के बाद छात्र के परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने शिक्षक लोकेश्वर निषाद के खिलाफ धारा 115(2) और 296 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस घटना से स्कूल के छात्र-छात्राओं में दहशत का माहौल है।

छत्तीसगढ़	प्रमुख समाचार	प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं प्रवेश हेतु 5 अगस्त तक	युवक ने खुद का काटा गला बचाने आई पत्नी पर ब्लेड से हमला	कांकेर की डीएसपी कविता धुवे ने जीता स्वर्ण पदक	ब्रॉन्ज मेडल विजेता खिलाड़ी का हुआ भव्य स्वागत	जनमन योजना ने बदली कवर्धा के वनांचल गांव की तस्वीर
		गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास), जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही द्वारा सूचना जारी की गई है। जारी सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत पात्र विद्यार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in/ पर प्रदर्शित कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग 22 जुलाई से शुरू हो गया है, जो 5 अगस्त 2026 तक चलेगा। काउंसिलिंग का आयोजन सूची में आवंटित प्रयास आवासीय विद्यालयों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने सभी चयनित छात्र-छात्राओं एवं उनके पालकों से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील की है।	जगदलपुर। दरभा थाना क्षेत्र में एक चाँकाने वाली घटना सामने आई है। यहां ग्राम कमनार में एक मानसिक रूप से परेशान युवक ने बुधवार को ब्लेड से अपना गला काट लिया। जब उसकी पत्नी उसे बचाने आई, तो युवक ने उस पर भी ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम कमनार निवासी 35 वर्षीय विषम नाग खेती-किसानी के साथ राजमिस्त्री का काम भी करता है। विगत एक माह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही थी। इस मानसिक परेशानी के चलते वह काफी परेशान चल रहा था। बीती शाम विषम ने घर में रखे ब्लेड से अपने गले को काटने का प्रयास किया। उसी समय उसकी पत्नी फगनी ने यह देख लिया। फगनी अपने पति को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। पति विषम ने अपनी मानसिक स्थिति के कारण पत्नी पर भी ब्लेड से हमला कर दिया। उसने पत्नी फगनी के गले में ब्लेड से वार किया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे।	कांकेर। 14 वीं सीनियर राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप-2026 में कांकेर जिले की बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है। मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित चैंपियनशिप में डीएसपी कविता धुवे ने शानदार प्रदर्शन किया और मास्टर्स 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। इस उपलब्धि से कांकेर, बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा है। शिलांग में आयोजित 14 वीं सीनियर राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप-2026 में कांकेर की महिला पुलिस अधिकारी कविता धुवे ने हिस्सा लिया था। मास्टर्स 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर वह लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय चैंपियन बनी हैं। पुलिस अधीक्षक ने डीएसपी कविता धुवे को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ही राष्ट्रीय स्तर पर सफलता मिलती है। कांकेर पुलिस ने जिलेवासियों की ओर से डीएसपी कविता धुवे को स्वर्ण पदक जीतने पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और आगामी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की।	धमतरी। स्वीडन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स गोथिया कप 2026 में फुटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व कर कांस्थ पदक जीतने वाले विशेष खिलाड़ी सत्यांशु दीप के गृह जिले लौटने पर उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। शहर में जगह-जगह फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन हुआ, जबकि सार्थक स्कूल में उनके सम्मान में भव्य समारोह आयोजित कर उनकी इस उपलब्धि का जश्न मनाया गया। सत्यांशु की कामयाबी ने न केवल धमतरी, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सार्थक स्कूल पहुंचते ही सत्यांशु दीप का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उनकी आरती उतारी गई, केक काटकर जीत का जश्न मनाया गया और सभी ने उनका मुंह मीठा कराया। समारोह का सबसे भावुक और आकर्षक पल तब आया, जब उनके नाम से जुड़े दीप को प्रतीकात्मक रूप देते हुए दीप प्रज्वलित कर उनकी सफलता का उत्सव मनाया गया। स्कूल के दिव्यांग एवं विशेष बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत कर पूरे माहौल को उत्साह और गर्व से भर दिया।	कवर्धा। जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत बनाई गई पक्की सड़क ने ग्रामीणों की वर्षों पुरानी आवागमन की समस्या का समाधान कर दिया है। जहां पहले बरसात के दिनों में कीचड़ और उबड़-खाबड़ रास्तों के कारण पैदल चलना भी मुश्किल होता था, वहीं अब इसी मार्ग पर वाहन आसानी से फरटते भर रहे हैं। इससे ग्रामीणों का सफर सुरक्षित, सुगम और तेज हो गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बांटीपथरा से पट्टियाधरान तक लगभग 3 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण 143.82 लाख रुपये की लागत से किया गया है। इस सड़क से जुड़े लगभग 135 बसाहटों के लोगों को वर्षभर आवागमन की सुविधा मिल रही है। अब ग्रामीणों को स्कूल, अस्पताल, बाजार और शासकीय सेवाओं तक पहुंचने में पहले जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ग्राम बांटीपथरा निवासी राजेन्द्र कुमार मरकाम ने बताया कि पहले बारिश के मौसम में गांव से बाहर निकलना बेहद कठिन हो जाता था।

आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित होने का आरोप

बिलासपुर में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 7 साल से लंबित मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन करते हुए कहा कि अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है,लेकिन समाधान नहीं निकला।

आपको बता दें कि पिछले सात साल से अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने एक बार फिर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर खींचा है। प्रदेश के सभी 33 जिलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिलाधीशों के माध्यम से



मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की। पुनरीक्षित वेतनमान, पदोन्नति, समयमान वेतनमान, जोखिम भत्ता, आवास सुविधा,

संविदा कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन और रिक्त पदों पर भर्ती जैसी मांगें वर्षों से लंबित हैं। 2023 के आंदोलन के दौरान मिले आश्वासन के बावजूद अब तक कोई ठोस

कार्रवाई नहीं हुई है - विकास शुक्ला,जिलाध्यक्ष,प्रदेश कर्मचारी संघ

संघ ने स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण, ठेका प्रथा ,आउटसोर्सिंग का भी विरोध करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य आयोग के गठन, हेल्थ सेक्टर में अनिवार्य पंजीयन व्यवस्था और रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की मांग भी उठाई गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।

पारंपरिक के बजाय रोजगारोन्मुखी कोर्स को दे रही प्राथमिकता

जगदलपुर। बस्तर की बेटियां अब पारंपरिक तकनीकी पाठ्यक्रमों से आगे बढ़कर ऐसे कोर्स चुन रही हैं, जिनमें रोजगार की संभावनाएं अधिक हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जगदलपुर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में देखने को मिल रहा है। जहां मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की सभी 31 सीटें प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही भर चुकी हैं। वहीं फैशन डिजाइनिंग में भी 30 में से 21 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पारंपरिक तकनीकी कोर्स में युवतियों की रुचि घट रही है।इसमें 45 सीटों के लिए केवल 2 छात्राओं ने ही प्रवेश लिया है।



महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य संजय त्रिवेदी ने बताया कि इस वर्ष मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट को लेकर छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। कोर्स की सभी 31 सीटें भर चुकी हैं। फैशन डिजाइनिंग में भी अच्छी संख्या में प्रवेश हुए हैं। जबकि आईटी में 30 में से 12 सीटें भरी हैं। लेज में प्रवेश ले चुकी छात्रा का पलक बघेल

कहना है कि मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स पूरा करने के बाद सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं। स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट सेक्टर में इसकी अच्छी मांग होने के कारण छात्राएं इस कोर्स को प्राथमिकता दे रही हैं। ताकि पढ़ाई के बाद उन्हें जल्दी रोजगार का अवसर प्राप्त हो

सके- पलक बघेल, छात्रा छात्रा मुस्कान नाग का कहना है कि सीटें सीमित होने से कई इच्छुक छात्राएं प्रवेश से वंचित रह जाती हैं। सरकार और तकनीकी शिक्षा विभाग से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की सीटें बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो अधिक से अधिक बेटियां इस कोर्स का लाभ उठाकर अपने भविष्य को नई दिशा दे सकेंगी। वहीं छात्रा सावनी मौर्य ने कहा कि वो भी स्खरूकी छात्रा है। आपको बता दें कि रोजगार की बढ़ती संभावनाओं ने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट को बस्तर की युवतियों की पहली पसंद बना दिया है।

संक्षिप्त समाचार

राहुल गांधी देश और संविधान से ऊपर नहीं, कानून सबके लिए एक समान: साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज कहा कि, भाजपा द्वारा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के घेराव के समय कांग्रेस ने जिस तरह का रवैया अपनाया वह बहुत दुर्भाग्यजनक है। पता नहीं कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, सत्ता से बाहर होने पर हताशा में दुर्व्यवहार का रास्ता अखिয়ার कर ली है। साव ने कहा कि, जब ये सरकार में होते हैं तो ये सत्ता का दुरुप्रयोग करते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान कांग्रेसी जिस प्रकार से डंडे लहरा रहे थे, सामने में आकर नारे लगा रहे थे ऐंसा कर वे क्या बताना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि, अपने नेता को जांबाज बताते हैं। जो नेता मान्य परंपरा, कानून व्यवस्था, संविधान से परे जाकर आचरण करता है, उसे जांबाज बताते हैं। वहीं जांबाजी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अब पुलिस प्रशासन को धमकाने का काम कर रहे हैं। साव ने कहा कि, सूरजपुर की घटना के दौरान इनके नेताओं ने पुलिस को धमकाया और अब ये फिर धमका कर क्या साबित करना चाहते हैं। इनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। सभी के लिए कानून समान है। सभी को कानून सम्मत आचरण करना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस न संविधान मानती है, न कानून मानती है। देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है।

कृषि विवि के कुलपति चंदेल बने राष्ट्रीय बायोटेक पार्क समिति के सदस्य

रायपुर। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश में जैव प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए संचालित राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना के तहत विभिन्न राज्यो में जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की जा रही है। इन जैव प्राद्योगिकी पार्कों की स्थापना राज्यो के सहयोग से की जा रही है। इन जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के लिए वितीय सहायोग उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्टीय स्तर पर गठित स्टीयरिंग सह प्रोजेक्टर मॉनीटरिंग समिति में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल को सदस्य बनाया गया है। यह समिति विभिन्न बायोटेक पार्कों के परियोजना प्रतिवेदन को मंजूरी देने के साथ ही उनके क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग भी करेगी।

आकाशीय विजली से मृतक की पत्नी को मिली 4 लाख की मुआवजा सहायता

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर संचालित मुख्यमंत्री कैप कार्यालय बगिया एक बार फिर ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत का माध्यम बना है। आकाशीय बिजली गिरने से मृत व्यक्ति की पत्नी द्वारा मुख्यमंत्री कैप कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लाख रुपये की मुआवजा सहायता राशि स्वीकृत कर उनके बैंक खाते में अंतरित करवाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम झरन (मसरिघाट), पोस्ट घुमरा, तहसील तपकरा, जिला जशपुर निवासी श्रीमती मुनिका बाई विश्वकर्मा के पति की आकाशीय बिजली गिरने से असामयिक मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद लंबे समय तक मुआवजा राशि प्राप्त नहीं होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री कैप कार्यालय बगिया में आवेदन प्रस्तुत कर सहायता की मांग की थी। आवेदन प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री कैप कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन ने प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और आवेदिका के बैंक खाते में 4 लाख रुपये की मुआवजा सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया। आर्थिक सहायता मिलने पर श्रीमती मुनिका बाई विश्वकर्मा एवं उनके परिजनो ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कैप कार्यालय की त्वरित पहल से उनकी लंबे समय से लंबित समस्या का समाधान हुआ। संकट की इस घड़ी में मिली सहायता से परिवार को बड़ा आर्थिक संवल प्राप्त हुआ है।

किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सतत निगरानी

रायपुर। खरीफ 2026 के दौरान डीएपी की राष्ट्रीय स्तर पर सीमित उपलब्धता के बावजूद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश के प्रत्येक किसान को समय पर खाद-बीज उपलब्ध हो, किसी भी किसान को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और उर्वरकों की कालाबाजारी अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी के अनुरूप कृषि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण एवं मूल्य नियंत्रण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीफ सीजन 2026 के लिए डीएपी का लक्ष्य 3 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। जबकि 21 जुलाई 2026 की स्थिति में प्रदेश में एक लाख 84 हजार 413 मीट्रिक टन डीएपी का भंडारण किया गया है। वहीं भंडारण के विरुद्ध किसानों को एक लाख 26 हजार 360 मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। इसके बाद भी समितियों एवं गोदामों में अभी 58 हजार 054 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हर घर नल-जल जीवन मिशन की प्रगति पर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस सम्पन्न

प्रत्येक परिवार तक सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना लक्ष्य: मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर घर नल (जल जीवन मिशन) की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य प्रत्येक परिवार तक सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना से महिलाओं का समय बचेगा और जलजनित बीमारियों में कमी आएगी तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में मिशन मोड में कार्य करते हुए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की



जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि वे प्रत्येक बिलों के भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य बाधित नही हो। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वीबी-जी राम जी और हस्तांतरित योजनाओं के भुगतान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन

योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका 31 अगस्त तक भौतिक सत्यापन कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जिन योजनाओं का कार्य अधूरा है, उन्हें 31 दिसंबर तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला कलेक्टर समयबद्ध तरीके से रनिंग बिलों के भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करें, जिससे निर्माण कार्य बाधित नही हो। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वीबी-जी राम जी एवं स्थानीय संसाधनों, जिला खनिज न्यास

(डीएमएफ), सांसद निधि, विधायक निधि, सीएसआर एवं अन्य उपलब्ध स्रोतों से आवश्यक वित्तीय व्यवस्था कर योजनाओं को पूर्ण किया जाए। उन्होंने प्रत्येक जिले को जलस्रोतों का आकलन कर नए स्रोतों की पहचान करने, जलस्रोत संरक्षण एवं रिचार्ज व्यवस्था विकसित करने तथा प्रत्येक स्रोत के संरक्षण की कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में वर्तमान स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराना संभव नहीं है, उनके लिए वैकल्पिक स्रोतों की पहचान कर शीघ्र कार्रवाई की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेयजल से वंचित नहीं रखा जा सकता। बैठक में सोलर आधारित नल जल योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि योजना-वार विश्लेषण कर स्वीकृत राशि एवं व्यय का समुचित मिलान किया जाए। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने

प्रत्येक जिले को हर घर जल के लिए नया लक्ष्य निर्धारित करने एवं गांवों को इकाई मानकर शत-प्रतिशत नल जल कवरेज सुनिश्चित करने तथा जिला जल एवं स्वच्छता समिति की नियमित मासिक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का समय पर विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाए तथा जल जीवन मिशन की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर स्पष्ट आकलन, बेहतर योजना और प्रभावी समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करें, ताकि राज्य के प्रत्येक परिवार को समयबद्ध रूप से हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, सभी जिलों के कलेक्टर एवं विभागीय अधिकारी शामिल हुए।

भाजपा और पुलिस पर भड़के भूपेश हद में रहने की दी चेतावनी

रायपुर। राजधानी रायपुर में भाजपा के कांग्रेस कार्यालय घेराव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है। बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा वालों को हद में रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बुधवार को घेराव के नाम पर भाजपा के लोगों ने रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय पर हमला किया है। इसमें भाजपा के सारे मंत्री भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं को ताक में रखकर शामिल हुए।

भूपेश बघेल ने कहा, आदतन उपद्रवी इन तत्वों



ने कांग्रेस मुख्यालय और हमारे कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके। पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी। सारा हमला भाजपा और पुलिस की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संवैधानिक मर्यादाओं को ताक में रखकर शामिल हुए। पत्रकार साथियों को भी चोटें आईं और पुलिस ने एफआईआर भी हमारे ही लोगों पर दर्ज कर ली।

वित्त मंत्री ने चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर किया नमन

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महातयक, अदम्य साहस एवं अद्वितीय राष्ट्रभक्ति के प्रतीक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर उन्हें विनम्र नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका अदम्य साहस, अटूट आत्मविश्वास और राष्ट्रप्रेम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद जी ने अपने संघर्ष, त्याग और बलिदान से देश के युवाओं में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और राष्ट्रसेवा की अलख जगाई। उनका जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए साहस, कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्ति की प्रेरणा का स्रोत है।

नेताओं पर एफआईआर की कांग्रेस ने की निंदा, बताया सरकार की फांसीवादी नीति

■ **भाजपा का पलटवार, कहा- हर अपराध के पीछे ये लोग**

रायपुर। भाजपा के कांग्रेस मुख्यालय घेराव के दौरान हुए बवाल में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने विरोध करते हुए इसे सरकार की फांसीवादी नीति बताया। वहीं भाजपा ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि हर अपराधों के पीछे कांग्रेस के लोग मिलते हैं।

कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर कहा कि कल सरकार के साथ बीजेपी के लोगों ने राजीव भवन पर हमला बोला था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े। कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। हम इस मामले को लेकर राज्यपाल के पास जाएंगे।

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद दुबे ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने जुते-चप्पल और पत्थर फेंके गए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को खिलफा ही एफआईआर दर्ज हो गया। यह फांसीवादी नीति है।



के लोग ट्रैक्टर में पत्थर भरकर लाए थे। सत्ता पक्ष होकर अपने गुंडों को लाकर कांग्रेस भवन में पत्थर फेंका गया। कांग्रेस नेताओं के ऊपर एफआईआर की हम आलोचना करते हैं। प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करें।

मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने कल जो रवैया अपनाया वह दुर्भाग्यजनक है। बीजेपी के आंदोलन के दौरान कांग्रेसियों ने डंडे लहराए। कांग्रेस पुलिस प्रशासन को धमकाने का काम कर रही है, लेकिन इनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। गुंडे किस पार्टी में हैं हमने बखूबी देखा है। हर अपराधों के पीछे कांग्रेस के लोग मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क हो या सदन, कांग्रेसियों का आचरण ऐसा ही है। कांग्रेसियों के आचरण की सजा प्रदेश की जनता जरूर देगी।

कांग्रेस के दफ्तर में आकर मंत्रियों के द्वारा प्रदर्शन करना शोभा नहीं देता। बीजेपी

■ **कार्रवाई के लिए दिया 15 दिन का समय**

रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में पदस्थ उप सचिव अंशिका पाण्डेय के स्थानांतरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने शासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। संघ ने विभाग के सचिव को स्मरण-पत्र सौंपते हुए कहा है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर स्थानांतरण संबंधी निर्णय नहीं लिया गया, तो कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं वैधानिक तरीके से आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा।

संघ के अध्यक्ष चन्द्रकांत पाण्डेय ने स्मरण-पत्र के जरिए बताया कि अंशिका पाण्डेय पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय से मंत्रालय (महानदी भवन) में पदस्थ हैं। संघ का दावा है



कि यह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 23 फरवरी को जारी परिपत्र की भावना के विपरीत है, जिसमें सामान्यतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक ही स्थान पर लंबे समय तक पदस्थ रहने से बचने का प्रावधान किया गया है।

संघ ने यह भी उल्लेख किया है कि इस विषय पर 23 जून को मुख्य सचिव को विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें विभिन्न तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर स्थानांतरण की मांग की गई थी। संघ का कहना है कि एक माह से

अधिक समय बीत जाने के बावजूद इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे मंत्रालय के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

स्मरण-पत्र में कहा गया है कि मंत्रालय में पारदर्शी, निष्पक्ष एवं जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। संघ का मत है कि स्थानांतरण नीति का समान रूप से पालन होने से प्रशासनिक निष्पक्षता और कर्मचारियों का विश्वास दोनों सुदृढ़ होंगे।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो वह लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक दायरे में रहकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करेगा। संघ का कहना है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक परिस्थितियों की जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बदली अशोक गुप्ता के घर की तस्वीर

■ **सोलर ऊर्जा से बिजली बिल में आई बड़ी राहत, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए लोगों को किया प्रेरित**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घररूप मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रदेशभर में आम नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। जशपुर जिले में भी यह योजना लोगों के बिजली खर्च को कम करने के साथ-साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम बन रही है। जशपुर जिले के हितग्राही श्री अशोक कुमार गुप्ता ने योजना के तहत अपने घर की छत पर रूपटॉप सोलर प्लांट स्थापित करवाया है। उन्होंने बताया कि पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल काफी अधिक आता था, जिससे नियमित आर्थिक बोझ बना रहता था। सोलर प्लांट लगने के बाद बिजली खर्च में उल्लेखनीय



कमी आई है और अब बिजली बिल की चिंता लगभग समाप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल सूर्य की ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करता है। घरेलू उपयोग के बाद बची हुई बिजली विद्युत वितरण कंपनी के ग्रिड में चली जाती है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। इस व्यवस्था के कारण उनका मासिक बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है।

श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही

है। यह योजना बिजली बिल में बचत के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा अपनाकर प्रत्येक परिवार बिजली खर्च में बचत के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकता है।

विकास भी, विरासत भी मोदी के 12 वर्षों की सौगात

तरुण युग

17 जुलाई, 2026 का दिन देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विश्व को भारत के श्रमिकों, इंजीनियरों की मेहनत की पराक्राष्ट, पराक्रम और तकनीक की धमक सुनाई, कुरुक्षेत्र में भव्य सिख संग्रहालय की आधारशिला रखकर गुरु परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया और फिर जालंधर की पावन धरती से पंजाब को 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के करोड़ों श्रद्धालुओं की दशकों पुरानी मांग पूरी करते हुए बेगमपुरा के बाद अब दूसरी ट्रेन छेहटी (अमृतसर) से काशी तक ‘संत गुरु रविदास एक्सप्रेस’ का शुभारंभ हुआ और 100 करोड़ की लागत से बना हुआ जालंधर कैंट का एयरपोर्ट जैसा भव्य रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित हुआ। आज जब पंजाब 2027 की दहलीज पर खड़ा होकर अंगड़ाई ले रहा है, तो हर पंजाबी के मन में 3 प्रश्न हैं–बीते 12 वर्षों में मोदी जी ने पंजाब को क्या दिया ? ‘आप’ के कुशासन ने पंजाब का क्या हाल कर दिया और पंजाब का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है ? इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पंजाब की दिशा और दशा तय करेंगे। 26 मई, 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दिन से ही मोदी जी ने पंजाब को केवल एक सीमावर्ती राज्य नहीं, बल्कि गुरुओं, महत्तामाओं, संतों, राष्ट्रभक्तों और शहीदों की पवित्र भूमि माना है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कतरापुर साहिब कॉरिडोर है। नवंबर 2019 में कॉरिडोर खुला और आज लाखों श्रद्धालु बिना वीजा के दर्शन कर घर लौटते हैं। सितम्बर 2020 में श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर को एफ.सी.आर.ए. पंजीकरण मिला, जिससे 1984 के 36 साल के बाद पहली बार विदेशों में बैट्री संसात सीधे गुरु घर की सेवा में दान भेज पा रही है। सेवा भोज योजना के अंतर्गत लंगर की सामग्री पर लगने वाले जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति कर केंद्र सरकार ने एस.जी.पी.सी. और दुर्गयाणा तीर्थ को करोड़ों रुपए लौटाए, गुरु के लंगर को कर–मुक्त किया। 925 करोड़ रुपए की लागत से 750 बिस्तरों वाला एम्स बठिंडा, मोहाली में टाटा कैंसर संस्थान, आई.आई.एम. अमृतसर, आई.आई.टी. रोपड़ का विस्तार, पी.जी.आई.एम.ई.आर. चंडीगढ़ का लगभग 1,000 करोड़ रुपए का सारंगपुर विस्तार परिसर और होशियारपुर कपूरथला में नए मैडिकल–नर्सिंग कॉलेज–मोदी जी ने पंजाब में स्वास्थ्य और शिक्षा की पूरी क्रांति खड़ी कर दी। कनेक्टिविटी में तो युग बदल गया–40,000 करोड़ रुपए का दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली से माता वैष्णो देवी का 16 घंटे का सफर घटाकर लगभग 6 घंटे और अमृतसर का सफर लगभग 4 घंटे कर देगा। ब्यास दरिया पर देश का सबसे लंबा केबल–स्टेड पुल बन रहा है। पंजाब में 43,527 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग और लगभग 34,000 करोड़ रुपए का रेलवे अवसंरचना निर्माण चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना में पंजाब के 30 स्टेशन शामिल हैं। अन्नदाता के सम्मान में पंजाब के 11 लाख किसानों के खातों में पी.एम.–किसान की राशि सीधी पहुंच रही है, गरीब कल्याण के तहत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगभग 1.40 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिल रहा है, शौचालय, पक्के घर, उज्ज्वला और आयुष्मान ने आम परिवारों का जीवन बदला है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जो हर पंजाबी का कलेजा चीर देती है। जिस पंजाब को केंद्र सरकार फफंदे दे रही है, उसी पंजाब को भावगत मान सरकार ने हर क्षेत्र में पीछे धकेल दिया है। सबसे बड़ा घाव शरी का है–आज पंजाब ड्रग्स के दरिया में डूबा कराह रहा है।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्याय: (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे....)

अत: अर्को वर्ष पूर्व तादृश रूप में विद्यमान होने वाले पदार्थ को आज भी वैसी स्थिति में प्रत्यक्ष देखने की अभिलाषा रखने वाले सज्जनों को कुछ प्राकृतिक परिवर्तन का भी मनन करना चाहिये।

कविवर भवभूति ने अपने प्रसिद्ध नाटक उत्तर रामचरित में जन–स्थान को देख कर श्री रामचन्द्र जी के शब्दों में प्राकृतिक परिवर्तन का एक बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा है, हम पाठकों के लाभार्थ यहाँ उसे उपस्थित करते हैं। आपने दृष्टपूर्व तत्तत् पदार्थों को लक्ष्य करके कहा कि–

पुरा यत्र स्रोत: पुलिनमधुना तत्र सरितां विपर्यासं यातो घनविलभाभव: क्षितिरहम्। बहोदृष्टं कालादपरमिव मन्ये वनमिदं निवेश: शैलानां तर्दिमति बुद्धि द्रढयति ।।

(उत्तररामचरित 2 । 27)

अर्थात्– पहले कुछ वर्ष पूर्व जहाँ झरनों की

श्रवण–रमणीय हर–हर ध्वनि होती थी आज वहां उन्नाल तरङ्गों को उछालती हुई नदियों के विशाल किनारे नजर आ रहे हैं। जहाँ हरे हरे संकुलित घने जंगल थे वे स्थान आज लहलही लतिकाओं से आच्छादित हो रहे हैं। अहो! श्राज मुदत्त के बाद देखा हुआ यह जनस्थान मुझे अदृष्टपूर्व विलक्षण सा ही दिख रहा है, परन्तु जहाँ तहाँ पर्वतों का जो यथावत् विन्यास है वही केवल इसके दृष्टपूर्व जनस्थान होने की सम्भावना को दृढ़ कर रहा है।

यह कोरी कविकल्पनामात्र ही नहीं है किन्तु तथ्य भी यही है। वृन्दावन में यमुनाघाट व्यर्थ से हो प्रवाहित हो रही है जहाँ कि कभी आज एक शताब्दी के अन्दर बने दृष्टे गये हैं, यमुना की बार आज वहाँ उत्तम उद्यान विद्यमान होंगे किंवा क्यूओं से खेती हुआ करती होगी। आज वे उजाड़ प्राय: घाट तथा यमुना के अन्दर आये हुये कूचे दिल खोल कर इस प्राकृतिक परिवर्तन की साक्षी दे रहे हैं।

क्रमश: ...



आशुतोष गर्ग

राजा नहुष और उनकी पत्नी विरजा के छह पराक्रमी पुत्र थे–यति, ययाति, संयाति, आयाति, धव और सुयाति। इनमें सबसे बड़े यति ने राजसुख त्यागकर वैराग्य का मार्ग अपनाया और तपस्वी बन गए। उन्होंने ककुत्स्थ की पुत्री गौ से विवाह किया, किंतु बाद में मोक्षधर्म का अनुसरण करते हुए जीवन ब्रह्मस्वरूप मुनि के रूप में बिताया।

यति के बाद संयाति राजा बने। उन्होंने अपने पराक्रम से पूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। उनका विवाह शुकाचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। देवयानी से यदु और तुर्वसु उत्पन्न हुए, जबकि शर्मिष्ठा से द्रुह्यु, अनु और पुरु का जन्म हुआ। ययाति अत्यंत साहसी थे। उनके अद्भुत पराक्रम से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ण निर्मित एक



लगाए गए ब्लॉकेड के जवाब में यह ब्लॉकेड लगा रहे हैं। यह भी स्ट्रीट ऑफ हॉमोस की तरह ही एक अहम ग्लोबल शिपिंग पॉइंट है। दुनिया का लगभग 15% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हूितियों ने अभी केवल सऊदी के जहाजों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। बाकी किसी जहाज पर कोई भी पाबंदी नहीं है। पर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। स्टेट ऑफ फार्मास बंद होने के बाद सऊदी अरब के तेल एक्सपोर्ट के लिए बाब अल-मंदेब अहम रास्ता बन गया था। ऐसे में अगर सऊदी का व्यापार वहां से रुकता है तो तेल की सप्लाई में और भी ज्यादा कमी आ जाएगी। न्यूज़ एंजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बाबल मंदीप स्टेट को पूरी तरह बंद करने से ग्लोबल तेल सप्लाई 7% तक कम हो जाएगा। इस बीच अमेरिका ने पहली बार ईरान के साथ दोबारा शुरू हुई झड़प में घायल हुए सैनिकों की जानकारी दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि 7 जुलाई से अब तक लगभग 100 सैनिक घायल हुए हैं। पेंटागन ने अमेरिकी मीडिया की ओर से घायल सैनिकों की जानकारी छिपाए जाने के आरोप के बाद यह जवाब दिया है। मीडिया में कहा जा रहा था कि सरकार ना तो अपने बुलेटिन में घायल सैनिकों की जानकारी दे रही है और ना ही यह बता रही है कि कितने हथियार खर्च किए हुए हैं। पेंटागन ने इन आरोपों से इंकार किया है। कहा है कि हाल में घायल सैनिकों में से अधिकतर को मामूली चोटें आई थी। 96% से ज्यादा सैनिक सर्विस पर वापस लौट भी आए हैं।

ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में

ज्ञान/मीमांसा

जंतर-मंतर के मुखौटों के पीछे का सच!

कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल

चाहे नीट हो याकि कोई भी एग्जाम हो, जो भी स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं उन्हें कठोरतम दंड मिलना ही चाहिए। कोई भी दोषी बख़्श नहीं जाने चाहिए। किसी भी एग्जाम में जालसाज़ी, पेपरलीक जैसे घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने की संपूर्ण जवाबदेही सरकार की है। कोई व्यक्ति हो, संगठन हों। सबको अपनी–अपनी मांगों को लेकर विरोध करना चाहिए। आप इस्तीफा माँगिए। याकि जो भी संविधान सम्मत विरोध के शांतिपूर्ण तरीके हों, उन सबको करिए। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही भारत है। संवाद के रास्ते हमेशा ही खुले होने चाहिए। सरकार का ये उत्तरदायित्व भी है।

लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि— देश में अराजकता के संगठित कृत्य को आंदोलन कहकर स्वीकार कर लिया जाएगा। भारत के युवाओं को कॉकरोच कहकर अपमानित करने वाली इंटरनेशनल साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत में कॉकरोच शब्द और दिल्ली जंतर–मंतर कनेक्शन अब नए संदर्भ में अपरिचित नहीं रह गया है। सबसे पहले कुछ जमूराँ ने अमेरिकी में बैठकर– भारत के युवाओं को– भारत के सुप्रीम कोर्ट की ख़िलाफ़त में कॉकरोच कहा। फिर भाजपा और मोदी विरोध की पटकथा लिखी गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने मई 2026 में ये टिप्पणी फर्जी डिग्री के ज़रिए क्वालित करने वाले वकीलों पर की थी। इसका उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया था। लेकिन डीप स्टेट ने आम आदमी पार्टी के जमूराँ को आगे कर – भारत की न्यायपालिका के ख़िलाफ़ उकसाया। यहीं से कॉकरोच शब्द को भारत के युवाओं के माथे पर चस्पा करने की योजना को मूर्तरूप दिया गया।

आम आदमी पार्टी का जमूरा – दीपके भारत आया, इधर–उधर प्रदर्शन के लिए गया लेकिन धूप तक बर्दाश्त न कर पाया। तत्पश्चात एफसीआरए के विरोध में सोनम वांगचुक को अमेरिकी मूल की उनकी पत्नी –रेबेका नॉर्मन के ज़रिए प्रोटेस्ट का चेहरा बनाकर जंतर–मंतर के मैदान में भूख हड़ताल के लिए उतार दिया गया। जहां इमोशनली–सैंटीमेंट भुनाने के तमाम प्रयोजन रचे जाने लगे। नेपाल और बांग्लादेश जैसे सत्ता की रीजिम चेंज करने का खाका खींचा जाने लगा।



फिर मोदी विरोध के जितने भी इकोसिस्टम वाले चेहरे थे, वो सब बिल से बिलबिलाकर सामने आने लगे। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी कि कैसे भी करके दिल्ली में शाहीन बाग जैसे दो फैलाए जाएं। कन्वर्जन करने वाले गिरोह के वो लोग जो एफसीआरए की मार से चोटिल थे। उन्होंने जी भर के पैसे बहाए। तमाम पीआर एजेंसीज हायर की गईं। सेलीब्रिटीज कहे जाने वाले कौमी लोग— हिंदुत्व को Smash करने के लिए उतर आए। विदेशी और देशी पैसों से सोशल मीडिया कैंपेन को लॉन्च कर दिया गया। भावुक युवाओं ने भी देखा–सुनी ऐसी तमाम स्टोरीज सोशल मीडिया में शेर कीं। जबकि इस तथाकथित आंदोलन में शिक्षाविद्, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स कहीं नज़र नहीं आए। अगर स्टूडेंट्स नज़र आए भी तो उन्हें मंच पर कहीं स्थान नहीं मिला। सिर्फ़ कुछ हाईजैकर्स , कॉमेंडियन, नेता और भारत विरोधी –हिन्दुत्व विरोधी बातें कहने वाले चेहरे नज़र आए। कंटेंट क्रिएटर्स ही दिखते रहे।

प्रोफेशनल पीआर स्टाइल में प्रोटेस्टर्स का जमावड़ा हुआ। एआईएसएफ़, एसएफआई समेत तमाम ग़दार वामपंथियों का इकोसिस्टम एक्टिवेटे हुआ। जेएनयू–एएमयू की तर्ज पर अर्बन नक्सल गिरोह को जिहादी डफली सुनाई देने लगी।LGBTQ का प्रचार–प्रसार किया जाने लगा। हिन्दू ध्र्णा का परचम बुलंद किया जाने लगा। लेकिन इन जमूराँ में से कोई भूख हड़ताल का साहस न कर पाया जिससे तंग आकर खुद सोनम वांगचुक तक को ये कहना पड़ा कि– आप लोग यहाँ आकर टूंस–टूंस कर खा रहे हैं, मुझे यह देखकर बहुत दुःख होता है।

इतना ही नहीं ये जंतर–मंतर वाले कॉकरोच – दिन के बाद रात को एसी रूम में जाकर सोते थे। पार्टियाँ करने में जुट जाते थे। फिर अपने रूटीन में जुट जाते थे। अंततोगत्वा 18 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सफ़्दरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। किन्तु ये कॉकरोच, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से– सोनम अत्यंत प्रकाशमान दिव्य रथ प्रदान किया, जिसमें मन के समान वेगशाली, श्वेतवर्ण अश्व जुते हुए थे। वह स्वर्ण निर्मित रथ कहीं भी अवरुद्ध नहीं होता था। उसी रथ पर वह अपनी पत्नी को ब्याह कर लाए थे। उसी के द्वारा दुर्धर्ष राजा ययाति ने केवल छह रातों में संपूर्ण पृथ्वी, देवताओं और दानवों तक को जीत लिया था। वह दिव्य रथ परंपरा से सभी पौरव राजाओं के पास सुरक्षित रहा।

आगे चलकर कुरुवंशी परीक्षित–पुत्र इंद्रोत जनमेजय को गार्ग्य मुनि ने शाप दिया था, जिसके कारण वह रथ उनके पास से अदृश्य हो गया था। घटना यह थी कि गार्ग्य मुनि का एक पुत्र था, जो अत्यंत वालाचल था। उसे इंद्रोत जनमेजय ने मार डाला, जिससे उन्हें ब्रह्महत्या का पाप लगा।

वांगचुक को सरकारी अस्पताल से प्रायवेट अस्पताल में भर्ती कराने की ज़िद पर अड़े। दिल्ली हाईकोर्ट गए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि– सफ़्दरजंग अस्पताल से कहीं और शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहां उनकी समुचित देखभाल हो रही है।

20 जुलाई 2026 को बिना परमिशन के संसद मार्च करने का शाहीन बाग–सीएए दंगे वाली स्टाइल में अभियान चलाया गया। कांग्रेस, आप, समाजवादी पार्टी, भीम–मोम के गठजोड़, लेफ्ट पार्टियां, कन्वर्जन कराने वाले एनजीओ, अर्बन नक्सली, ब्रेकिंग इंडिया फ़ोर्सेज, सो–रोस–डीप स्टेट के वॉलंटियर्स – सब देश के यु्थ के कंधों पर बंदूक रखकर उतर आए। सबसे भीड़ जुटाने का पर्याप्त प्रबंध किया।

भाजपा और मोदी विरोध के सभी गिरोह एकजुट हुए। भरपूर पैसा बहाया गया। संसद घेरने के लिए भीड़ को उतार दिया गया। जिन क्षेत्रों में ड्रोन प्रतिबंधित थे, वहां शक्ति प्रदर्शन– प्रचार के लिए ड्रोन कैमरे चलाए गए। कंगमीर की तर्ज पर भीड़ के ज़रिए पुलिस पर संश्रमि योजना के तहत पथराव कराया गया। पुलिस वालों और महिला पत्रकारों की लिंविंग की कोशिशें की गईं। भारत के संविधान ने जिस संसद का गठन किया। जो संसद हमारे देश की सांविधानिक आधारशिला है। उसे उखाड़ फेंकने की बातें दुहराई गईं। भारत को नेपाल बनाने का कॉकरोचों ने दंभ भरा। ये तब हो रहा था जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इनके प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया और चर्चा की।

आप सोचिए कि– इस संगठित भीड़ ने जो उपद्रव किए क्या ये लोकतांत्रिक कृत्य हैं ? क्या ये किसी मांग को मनवाने की बातें हैं ? किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन में पत्थरबाजी कहां से होने लगी, अचानक से इतने पत्थर क्या बिना पूर्व तैयारी के आ गए ? क्या ये संगठित अराजकता– भारत की लोकतांत्रिक स्थिरता, प्रगति को रोकने के षड्यंत्र नहीं हैं ? ये षड्यंत्र उस युवा के सेंटिमेंट्स के ज़रिए क्रांति किए जा रहे हैं। जो भारत की प्रगति का आधार है। मैं भी युवा हूं और तथाकथित जेन–जी की परिभाषा में भी आता हूं। मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं। अपनी मांगों और विरोध के हमारे पास सांविधानिक तौर तरीके हैं। अपनी पीड़ा और आक्रोश की अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। लेकिन



अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ के अंत में स्नान करते ही उनका पाप नष्ट हो गया और शरीर से आने वाली लोहे की गंध भी समाप्त हो गई। इसके बाद प्रसन्न होकर इंद्र ने वह दिव्य रथ चेदिराज उपरिचर वसु को प्रदान कर दिया। उनसे वह रथ मगधराज बृहद्रथ, उनके पुत्र जरासंध और अंतंत: श्रीकृष्ण को प्राप्त हुआ। राजा ययाति ने संपूर्ण पृथ्वी को पांच भागों में विभाजित कर अपने पांचों पुत्रों में बांट दिया। दक्षिण–पूर्व का राज्य तुर्वसु को, पश्चिम द्रुह्यु को, उत्तर अनु को,

इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी मुझे भारत की स्थिरता के खिलाफ़ बरगला लेगा। क्या कोई भी टूल बनाकर हमें किसी आग में झोंक देगा और हम उसमें कूद पड़ेंगे ? ये हम युवाओं को सोचना और समझना चाहिए।

जंतर–मंतर में सोनम वांगचुक को बलि का बकरा बनाकर जिस शातिराना ढंग से भारत घ्रणा– हिन्दू घ्रणा का प्रहसन किया गया। उसे इस देश का युवा अच्छी तरह से जानता है। युवा साधियों को इसे और बारीकी से समझना चाहिए। ताकि हम किसी टूलकिट का शिकार न बनें। जंतर–मंतर में जिस तरह से भगवान राम को अपमानित किया गया। भारत की संस्कृति के खिलाफ़ ज़हर उगला गया। ब्राह्मणों, हिन्दुत्व को ख़त्म करने का ऐलान किया जाता रहा। आरएसएस के खिलाफ़ नारेबाजी की जाती रही। भारतीयता की बात करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 को ख़त्म करने की जिहादी पोस्टर बनाए गए। नारेबाज़ी की गई। काफ़िरों के कल्लेआम के लिए फ़ंज़ की बस नाम रहेगा अल्लाह का जैसा जिहादी ऐलान किया गया। यानी भारत के इस्लामीकरण का फतवा जारी किया गया।

क्या ये सब किसी भी हिसाब से जायज़ कहा जाएगा ? क्या ये किसी न्याय की लड़ाई थी ? पूरे प्रहसन के दौरान जिस तरीक़े से हर दिन भारत ट्रेष का विष वमन किया जाता रहा। संविधान और तिरंगे की ओट में छिपकर— भारत के संविधान को चुनौती दी जाती रही। भारत की न्यायपालिका को कठघरे में खड़ा किया जाता रहा। संसद को उखाड़ फेंकने के नारे गढ़े गए। भारत को —हिंसा, दंगों की आग में झोंकने के लिए — नेपाल बनाने के जो संदेश दिए गए। वो गंभीर हैं। हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती भी हैं। ये कोरी भावुकता तो कतई नहीं हो सकती। ये निश्चित ही भारत की शक्ति, सामर्थ्य के ख़िलाफ़ एक सुनियोजित साजिश है। इसमें सत्ता की भूख़ी राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता भी अव्वल हैं। जो बांग्लादेश और नेपाल हिंसा के बाद वहां हुए तख्तापलट के समय से ही – भारत के युवाओं को हिंसा, उपद्रव के लिए उकसा रहे हैं। कभी वो जेन–जी के नाम पर उकसाते हैं। कभी किसी मुद्दे के नाम पर, लेकिन उसका उद्देश्य है — सत्ता पाए। मोदी को सत्ता से हटाना। इसके लिए ये पार्टियां और नेता – भारत विरोध तक की सीमा पार कर रहे हैं। ऐसे में कॉकरोच के इस लॉन्विंग पैड के हर छोटे बड़े घटनाक्रम को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है।

जनमेजय को कैसे लगा ब्रह्महत्या-दोष?

ब्रह्महत्या के कारण पुरवासियों और जनपद के लोगों ने उनका त्याग कर दिया और उनके शरीर से लोहे जैसी दुर्गांध आती थी। वह इधर–उधर भटकते रहे, पर कहीं भी शांति नहीं मिली। तब दुखी होकर वह शौनक मुनि की शरण में गए। द्विजश्रेष्ठ शौनक ने उनके प्रार्थाश्रित के लिए

अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ के अंत में स्नान करते ही उनका पाप नष्ट हो गया और शरीर से आने वाली लोहे की गंध भी समाप्त हो गई। इसके बाद प्रसन्न होकर इंद्र ने वह दिव्य रथ चेदिराज उपरिचर वसु को प्रदान कर दिया। उनसे वह रथ मगधराज बृहद्रथ, उनके पुत्र जरासंध और अंतंत: श्रीकृष्ण को प्राप्त हुआ। राजा ययाति ने संपूर्ण पृथ्वी को पांच भागों में विभाजित कर अपने पांचों पुत्रों में बांट दिया। दक्षिण–पूर्व का राज्य तुर्वसु को, पश्चिम द्रुह्यु को, उत्तर अनु को,

आज का इतिहास

- 1834 पुर्तगाल में लिबरल युद्ध समाप्त हुआ।
- 1870 अमेरिका में पहली अंतरदेशीय रेल सेवा की शुरुआत हुई।
- 1910 ओटोमन बलों ने 1910 के ऑलब्रानिय विद्रोह को शांत करने के लिए शकोदर शहर पर कब्जा कर लिया।
- 1915 सेंट्रल सिकागो में एक स्टीमर ईस्टलैंड की वजह से 844 लोगों की जान गयी।
- 1923 लॉर्जेन की संधि को ओटोमन साम्राज्य के विभाजन के लिए एनाटोलियन पार्टीफ का निपटान करने के लिए हस्ताक्षर किया गया था, जिससे सीमा आधुनिक तुर्की की स्थापना हुई।
- 1929 फ्रांसीसी प्रधान मंत्री रेमंड पोंकारे ने इस्तीफा देने के बाद अरिस्तैड ब्रेंड को इसका उत्तराधिकारी बनाया गया।
- 1938 जर्मन–ऑस्ट्रियाई टीम की संयुक्त टीम एयर के उत्तरी चेहरे पर चढ़ाई करने वाली पहली टीम बन गई, जो एल्प्स के छह महान उत्तरी चेहरों में से एक है।
- 1941 उत्तर यूरोपीय देश लिथुनिया में सम्पूर्ण यहूदी आबादी की नाजियों ने हत्या की।
- 1944 300 लड़ाकू विमानों ने जर्मनी पर बम गिराए।
- 1959 सोवियत प्रीमियर निकिता ख्रूशेव और अमेरिकी उपराष्ट्रपति रिचर्डसन निक्सन ने मॉस्को के सोकोनिकी पार्क में अमेरिकननेशनल प्रदर्शनी के उद्घाटन पर एक गंभीर बहस की।
- 1967 मॉन्ट्रियल में एक भाषण के दौरान, फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉलडेक्लेर ने लॉन्ग लाइव फ्री क्यूबेक!, एक बयान दिया जिसमें कनाडा से क्यूबेक स्वतंत्रता के लिए आत्मसात किया गया था।
- 1982 जापान के नागासाकी में भारी बारिश से पुल ढहने से 299 लोगों की मौत हुई।
- 1994 असम के बसबारी में बोडो उग्रवादियों ने 37 मुस्लिमों की हत्या की।
- 1999 अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया का सफल प्रक्षेपण हुआ।
- 2002 रिश्तत लेने, आयकर की चोरी और धमकी देने के दोषी पाए जाने के बाद, जेम्स ट्रीफ़केंट को संयुक्त राज्य के प्रतिनिधि सभा से निष्कासित कर दिया गया था।
- 2005 लॉस आर्मस्ट्रांग अपने 7 वें सीधे टूर्स दी फ्रांस जीतने के बाद सेवानिवृत्त हुए।
- 2008 फ्रांस के ट्रिंकेस्टिन परमाणु संयंत्र में हुए रिसाव से लगभग 100 व्यक्ति प्रभावित हुए।
- 2010 व्यभिचार के लिए फांसी का सामना कर रही ईरानी महिला सकीना मोहम्मदी अस्थिनी को रिहा करने के लिए रैलियां पेरिस, न्यूयॉर्क शहर, ओटोवा और अन्य जगहों पर होती हैं।

क्या युवाओं पर केंद्रित हो रही है कांग्रेस की नई राजनीति?

जयसिंह रावत

लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस की उम्मीद राहुल गांधी की देहरादून में 17 जुलाई को आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम केवल एक राजनीतिक सभा नहीं थी। यह कांग्रेस की बदलती राजनीतिक प्राथमिकताओं और भविष्य की चुनावी रणनीति का ऐसा संकेत भी थी, जिसे केवल उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी पढ़े जाने की आवश्यकता है। राजस्थान के कोटा से प्रारंभ हुए इस अभियान का दूसरा बड़ा पड़ाव उत्तराखंड बना। यह चयन संयोग नहीं माना जा सकता।

पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, चयन प्रक्रियाओं पर सवाल, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं में गहराते असंतोष के कारण राष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा है। कांग्रेस ने इन्हीं परिस्थितियों को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने का प्रयास किया। कार्यक्रम का सबसे उल्लेखनीय कक्ष यह रहा कि राहुल गांधी ने अपने पूरे संबोधन को लगभग पूरी तरह पेपर लीक, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य तक सीमित रखा।

उन्होंने राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमलों के लिए उपलब्ध अनेक अन्य विवादित मुद्दों—महंगाई, अँकिता भंडारी हत्याकांड, बदरीनाथ धाम में दान राशि चोरी, दो कार्यकाल की एंटी-इंक्वेंसेंसी अथवा सामाजिक-राजनीतिक विवादों—को लगभग पूरी तरह अनदेखा किया। यह चयन स्वयं में

राजनीतिक संदेश देता है।

दरअसल, भाजपा और राज्य सरकार ने भी राहुल गांधी के संभावित राजनीतिक हमलों का पूर्वानुमान लगाया हुआ था। उत्तराखंड सैनिक परंपरा वाला राज्य है। बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते रहे हैं। माना जा रहा था कि राहुल गांधी अग्निवीर योजना को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। यही कारण था कि उनके कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले राज्य सरकार ने अग्निवीरों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया तथा राज्य स्तर पर अग्निवीर प्रकोष्ठ के गठन की घोषणा भी कर दी। राजनीतिक दृष्टि से यह एक प्रकार की पूर्व तैयारी थी।

किंतु राहुल गांधी ने इस विषय को छूने के बजाय अपना पूरा फोकस युवाओं की शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और रोजगार पर केंद्रित रखा। इससे यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस फिलहाल उन मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहती है, जिन पर उसे व्यापक सामाजिक सहमति और राजनीतिक स्वीकार्यता मिलने की संभावना दिखाई देती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों में अपनी राजनीति का स्वरूप लगातार बदलते दिखाई देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे विषयों को केंद्र में रखा था। अब %छात्रों की गूंज% अभियान में युवाओं और शिक्षा को प्रमुख



स्थान दिया गया है।

कोटा में उन्होंने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रिजेक्शन सिस्टम बताते हुए कहा था कि व्यवस्था छात्रों को अवसर देने के बजाय उन्हें बाहर करने का माध्यम बन गई है। देहरादून में भी उनके भाषण का मूल स्वर यही रहा कि शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती खाई युवाओं के भीतर गहरा असंतोष पैदा कर रही है। उत्तराखंड का चयन भी राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और अन्य चयन प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं ने हजारों युवाओं को प्रभावित किया। राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया, अनेक गिरफ्तारियां हुईं और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई भी की।

सरकार का दावा है कि उसने भर्ती प्रणाली को पहले की अपेक्षा अधिक पारदर्शी बनाया

है। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं है; युवाओं का विश्वास तभी लौटेगा जब समयबद्ध, निष्पक्ष और नियमित भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। यही वह राजनीतिक रफ़िक है, जिसमें कांग्रेस अपनी संभावनाएं तलाश रही है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राहुल गांधी का यह कार्यक्रम पारंपरिक विपक्षी राजनीति से कुछ अलग दिखाई देता है। सामान्यतः विपक्ष सरकार को घेरने के लिए उपलब्ध हर मुद्दे का उपयोग करता है। लेकिन देहरादून में राहुल गांधी ने अपेक्षाकृत संयमित रणनीति अपनाई।

उन्होंने आरोपों की सूची प्रस्तुत करने के बजाय एक ही विषय—युवाओं के भविष्य—पर लगातार बल दिया। इससे यह आभास मिलता है कि कांग्रेस फिलहाल अपने राजनीतिक संदेश को बिखरने देने के बजाय सीमित लेकिन प्रभावी मुद्दों पर केंद्रित रखना चाहती है।

इसके पीछे एक महत्वपूर्ण चुनावी गणित भी दिखाई देता है। भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में है। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।

बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी,

विमर्श के केंद्र में रखने लगे हैं, भले ही उनके समाधान और प्राथमिकताएं अलग-अलग हों।

देहरादून का कार्यक्रम एक और संकेत देता है। भारतीय राजनीति लंबे समय तक पहचान आधारित मुद्दों—जाति, धर्म, क्षेत्र और व्यक्तित्व—के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन अब रोजगार, शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और अवसरों की समानता जैसे विषय भी समानांतर रूप से राजनीतिक एजेंडा बनते दिखाई दे रहे हैं। यह परिवर्तन धीमा अवश्य है, परंतु महत्वपूर्ण है।

यदि राजनीतिक दल इन प्रश्नों को केवल चुनावी नारों तक सीमित रखने के बजाय ठोस नीतिगत बहस का हिस्सा बनाते हैं तो भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

अंततः देहरादून का छात्रों की गूंज कार्यक्रम केवल राहुल गांधी की एक सभा भर नहीं था। यह कांग्रेस की बदलती राजनीतिक प्राथमिकताओं की झलक भी था। पार्टी ने संकेत दिया है कि वह युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन शिक्षा, रोजगार और अवसरों के सवालों पर तैयार करना चाहती है। यह रणनीति कितनी सफल होगी, इसका उत्तर भविष्य देगा।

किंतु इतना स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण चुनावी प्रश्न केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि युवाओं का भविष्य, रोजगार की गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता भी होगा। यदि ऐसा होता है तो यह भारतीय लोकतंत्र के विमर्श में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जाएगा।

नेताओं की गिद्ध–दृष्टि से मुक्त हों मंदिर

विनीत नारायण

जबसे अयोध्या के श्रीराम मंदिर में भारी मात्रा में चढ़ावा चोरी की खबरें सामने आई हैं, तबसे देश के अन्य मंदिरों के भी ऐसे घोटाले रोज सामने आ रहे हैं। फिर वह चाहे जम्मु कश्मीर के माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का मामला हो, उत्तराखंड के केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम का हो या मध्य प्रदेश में ऊज्जैन के महाकाल का हो या आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम का हो, हर जगह से भारी मात्रा में रुपये व सोने-चांदी के चोरी के समाचार आ रहे हैं। सनातन धर्म के मंदिरों की संपत्ति पर सैकड़ों वर्षों से लुटेरों की गिद्ध–दृष्टि रही है। फिर वे चाहे यवन आक्रांता हों या देश के ही विभिन्न राज्यबंधों के हिंदू या बौद्ध राजा ही क्यों न हों या अंग्रेज हुकमरान और आजादी के बाद विभिन्न दलों के राजनेता। सबसे जब मौका मिला, मंदिरों की अरबों की संपत्ति को चुराया या लूटा है। कारण स्पष्ट है कि धर्म–प्रधान देश होने के कारण सनातन धर्म के मंदिरों में हमेशा से भावुक भक्त उदारता से सोना–चांदी, जमीन–जायदाद और हिरें–जवाहरात दान करते आए हैं। इस संपत्ति के प्रबंधन की कोई सुव्यवस्थित पारदर्शी व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है। हर मंदिर के संरक्षकों, सेवायों और भक्तों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार प्रबंधन की व्यवस्थाएं की जाती हैं। इस दिशा में जो सबसे प्रभावशाली उदाहरण है, वह दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य का है। चोल राजवंश ने तमिलनाडु और आसपास के भूभाग पर नौवीं से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक शासन किया। इन शासकों के कार्यकाल में विदेशों से व्यापार और देश में अच्छे उत्पादन के कारण बहुत संपन्नता आई। चोल राजाओं ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मंदिरों पर केंद्रित रखा। हर गांव, कस्बे और नगर की सभी आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, कलात्मक, शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र ये मंदिर हुआ करते थे। इन मंदिरों में लोकतांत्रिक प्रणाली से विभिन्न उद्देश्यों की

पूर्ति के लिए समितियों का गठन किया जाता था। जैसे सरोवरों का प्रबंधन, कर संग्रह, वनों का संरक्षण आदि, इन्हीं समितियों के दायित्व होते थे। इस तरह हर मंदिर स्थानीय समाज के नियंत्रण में काम करता था। इस आशय के जो शिलालेख मिले हैं, उनमें इन मंदिरों की कार्यप्रणाली का विस्तृत ब्योरा है। आज उपरोक्त अनेक क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी या गैर–सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। इसलिए मंदिर पूरे समाज की गतिविधियों का केंद्र नहीं हो सकते। पर धर्मस्थलों का प्रबंधन समाज की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन लोगों की होनी चाहिए, जो उस धर्मस्थल विशेष को नियमित रूप से उदारता से दान देते हैं। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा भाव से अपने श्रम अर्जित धन को उदारता से उस धर्मस्थल को दान देता है, वह उस धन की चोरी भी करेगा। ये हमारे संस्कारों में नहीं है। जो दैविक द्रव्य की चोरी करते हैं, वे चाहे आस्तिक होने का कितना ही आडंबर क्यों न रचें, निरे नास्तिक होते हैं। फिर वे चाहे किसी संगठन से जुड़े हों या राजनीतिक दल से। ऐसे लोगों को धर्मस्थलों के प्रबंधन से कोसों दूर रखना चाहिए। इनमें सरकारी अधिकारी और न्यायपालिका के सदस्य भी शामिल हैं। हर धर्मस्थल के प्रबंधन में प्रभावी मार्ग निर्देशक की भूमिका उस संप्रदाय के प्रतिष्ठित संतों की सूँपी भी चाहिए। इस पूरे तंत्र के ऊपर निगरानी रखने का दायित्व चारों मान्य शंकराचार्यों का होना चाहिए। उन आत्मघोषित फर्जी शंकराचार्यों या नए बनाए गए तथाकथित संतों का नहीं, जो किसी या किसी राजनीतिक दल या नेता द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। इसके साथ ही केंद्र या प्रांतों की सरकारों को धर्मस्थलों के प्रबंधन में या उनकी समितियों में अपने प्रतिनिधि नामित करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे नामित व्यक्तियों की जवाबदेही विराजमान देव विग्रह, उस संप्रदाय या उसके प्रतिष्ठित संतों के प्रति नहीं होती।

हार में जीत तलाशता ईरान, अब लड़नी होगी अधूरी जंग

एस प्रसन्नराजन

यह वही है, जो हम सबने सोचा। इस युद्ध में कोई नहीं जीता। अमेरिका और ईरान, दोनों की छवि को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के लिए यह नुकसान प्रतीकात्मक था, जबकि ईरान को अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत जैसी कीमत चुकानी पड़ी। नैरेटिव की लड़ाई में सिर्फ एक ही विजेता था–ईरान। अमेरिका–विरोधी भावना, यहूदी–विरोधी सोच और एक सभ्यता के प्रति गलत सोच के अजीब मेल ने एक बरुर शासन को ‘कमजोर होते हुए भी पलटवार करने वाले’ की छवि बनाने में मदद की। अमेरिका के खिलाफ हमेशा जारी रहने वाले संघर्ष की पुरानी कहानी के सहारे जीत का दावा करने वाला कोई बड़ा धर्मगुरु नहीं था। फिर भी, ईरान ने नैरेटिव की इस जीत को युद्धविराम के बाद भी लोगों को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल करने से खुद को नहीं रोका। ईरान ने समझौता इसलिए तोड़ा, क्योंकि वह ऐसा कर सकता था। अधूरे युद्ध के बाद दुनिया को देखने के अपने नजरिये से, ईरान अमेरिका को एक कमजोर या घटती हुई ताकत मानता है और उसके राष्ट्रपति को बड़ी–बड़ी बातें करने वाला धोखेबाज। ईरान का मानना है कि भले ही वह खुद नुकसान झेल चुका हो और घायल हो, फिर भी वह महाशक्ति देश को चुनौती दे सकता है। वहीं, ट्रंप ने खुद को हल्के में लेने दिया और ईरान ने दुनिया से यही संकेत लिया। दुनिया का लगभग हर नेता अमेरिकी राष्ट्रपति के अहंकार को साधने की कला में माहिर हो रहा है। वे ट्रंप के अचानक लिए गए फैसलों को समझने और उनकी समझदारी को कम आंकने का तरीका सीख रहे हैं। ईरान ने उन्का मजाक उड़ाने की हिम्मत दिखाई है।

ट्रंप के साम्राज्यवाद को सही ढंग से समझा गया है। वह एक ऐसे साम्राज्य के मुखिया हैं, जो उनके अपने अहंकार जितना ही बड़ा है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर एकमात्र संरक्षक के तौर पर ईरान का लौटना, राष्ट्रपति ट्रंप पर सीधा हमला है, जो युद्ध जीतने का दावा करते हैं। यह उस राष्ट्रपति को चुनौती देना था, जिन्होंने इस रास्ते को आजाद



कराने का वादा किया था, जो अमेरिका के लिए ऊर्जा–समृद्ध भविष्य के उनके विजन का अग्रम हिस्सा है। ट्रंप का विजन, खुद उनके इरादों के बावजूद, बाकी दुनिया की आर्थिक जरूरतों से मेल खाता है।

ईरान को लगता है कि इतिहास उसके साथ है, और ट्रंप से तंग आ चुकी दुनिया की भावनाएं भी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वह पहले ही अपने ज्यादातर नेताओं को खो चुका है। इसने जो चीज बरकरार रखी है, वह है एक सैन्य–इस्लामिक ढांचा, जिसे चार दशकों से अधिक समय में बेहद घातक और सटीक बनाया गया है। ईरान के पास यही एकमात्र मजबूत व्यवस्था है, और यह इतनी गहराई से जमी हुई है कि कोई भी युद्ध इसके फैलाव या इसके गुप्तनाम नेतृत्व के ढांचे को खत्म नहीं कर सकता। अमेरिका को निराश करने वाली ईरान की उस प्रतिक्रिया ने यह दिखाया कि कैसे ‘ईश्वर के क्रांतिकारी’ के मार्गदर्शन के बिना भी किसी युद्ध को बेअसर किया जा सकता है। ऐसा लग रहा था, जैसे फारसी लोककथाओं की कोई रहस्यमयी शक्ति बहुत बड़े पैमाने पर बुराई को काबू में कर रही हो।

यह अब भी वैसा ही है। ट्रंप भले ही दावा करें कि आक्रामक ईरान के खिलाफ हमले जारी रखने के लिए अमेरिका को युद्ध की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें उस व्यवस्था की असलियत का जरा भी अंदाजा नहीं है, जिसके साथ वह समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में एक ऐसी सरकार है, जिसमें कोई एक सर्वोच्च अधिकारी या आवाज नहीं है। उसके सभी प्रवक्ताओं की विश्वसनीयता बस एक होलोग्राम जैसी है। ईरान ने नैरेटिव की जो लड़ाई

जीती है, उससे वह शहादत को राष्ट्रीय ताकत और मलबे को स्मारक में बदल सकता है। यह बेचेहरा सरकार मानवीय जवाबदेही से मुक्त है, यहां तक कि धार्मिक वैधता का उसका दिखावा भी महज एक क्रांतिकारी मुछौटा है। उसकी यही खतरनाक आजादी न सिर्फ अमेरिकी ताकत का सामना करती है, बल्कि उसे नीचा भी दिखाती है।

लेकिन, इसका शिकार केवल अमेरिका या होर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी जान जोखिम में डालने वाले नाविक ही नहीं हैं। उन्हें तो कीमत चुकानी ही पड़ती है, साथ ही पूरे पश्चिम एशिया को भी। अमेरिकी हमले का बदला लेने के लिए आसान शिकार की तलाश कर रहा ईरान, खाड़ी क्षेत्र में पहले ही बेचैनी का माहौल बना चुका है। ईरान ने हमेशा एक साम्राज्यवादी देश के आत्मविश्वास के साथ अपनी आध्यात्मिक और सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। असल में और अपने रवैये में वह ऐसा ही था। उसने अपने पड़ोस के उन आतंकवादी संगठनों को हथियार और इस्लामी विचारधाराओं की आपूर्ति की, जो उन लोगों के प्रति भारी नफरत और उन्हें खत्म करने की भावना रखते थे, जिन्हें वे अपने अनुकूल नहीं मानते थे। फिर भी, हार में जीत खोजने वाला ईरान सिर्फ दुनिया की शांति के लिए ही खतरा नहीं है, अपने देश के लिए भी एक बड़ा खतरा है।

ट्रंप ने ईरानियों को धार्मिक तानाशाही से आजादी दिलाने का वादा करते हुए लड़ाई छेड़ी थी। इस तरह का नैतिक आदर्शवाद असल में पुरानी अमेरिकी सोच थी, जिसमें अपने फायदे और अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का मेल होता था। और यही वे ईरानी चाहते थे, जिन्होंने सत्ता को चुनौती दी और अंततः जेलों में या कब्रगाहों में जा पहुंचे। एक लड़खड़ाती क्रांति की भूख कभी नहीं मिटती और अतीत की सभी क्रांतियों की तरह, इसे बनाए रखने के लिए भी बागी लोगों के खून की जरूरत थी। ट्रंप उम्मीद जगाने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी उसने ऐसी उम्मीद कम ही थी। ईरान की अधूरी लड़ाई अब ईरानियों को ही पूरी करनी होगी। ट्रंप भी अपनी बातों पर टिक नहीं सके। उन्होंने ईरानियों को ऐसा मौका ही नहीं दिया कि वे अपनी क्रांति शुरू कर पाते।

रशीद किदवई

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के धरना व प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के बाद युवा वर्ग बेहद आहत है और ऐसे में राहुल गांधी की अगुआई में कांग्रेस के पास खुद को आगे बढ़ाने का एक अच्छा अवसर भी है। मगर सवाल यही है कि हर बार अच्छे अवसरों को गंवाने वाली कांग्रेस क्या इस बार सरकार के खिलाफ बने माहौल को अपने पक्ष में भुना पाएगी ?

दरअसल, यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस पूरे मसले पर राहुल गांधी ने धैर्य के साथ और एक सोची-समझी रणनीति के तहत काम किया है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तो करीब एक महीने से चल रहा है, लेकिन राहुल ने इससे दूरी बनाए रखी। कुछ लोग सवाल भी उठाते रहे कि आखिर सरकार विरोधी इस आंदोलन में राहुल खुद क्यों नहीं जा रहे? राहुल की सोच यह थी कि अगर वह सीजेपी के प्रदर्शन में चले गए, तो एक तो इसका पूरा फायदा उस संगठन को मिल जाएगा और दूसरा यह कि कांग्रेस स्वयं भी पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार विरोध दर्ज करा रही है, जिससे उसका अपना प्रतिरोध कमजोर पड़ सकता था। इसके अलावा, एक आशंका यह भी थी कि इसमें राहुल के कुदरे ही भाजपा या उसके समर्थक इस पूरे मुद्दे की दिशा ही मोड़ने का प्रयास करते।

अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस इस पूरे मसले को कितने प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाती है। देश का युवा पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। लेकिन, कांग्रेस के सामने बड़ी व्यावहारिक चुनौती यह है कि अधिकांश यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में या तो भाजपा समर्थित छात्र संगठनों का दबदबा है या वामपंथी छात्र संघों का। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई का प्रभाव अब वैसा नहीं रहा, जैसा कभी हुआ करता था। ऐसे में, केवल राहुल गांधी के व्यक्तिगत राजनीतिक उभार के बलबूते पार्टी इस मसले का कितना सियासी फायदा उठा पाएगी, उसी से उसकी सफलता तय होगी।

देश की राजनीति आज ऐसे मुकाम पर आ खड़ी है, जहां कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों को या तो साथ लेकर



चलना है या उन्हें सही ढंग से साधना है। छात्रों के इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी (आप) लगातार समर्थन दे रही है और वह सिर्फ भाजपा सरकार से ही नहीं, बल्कि कांग्रेस से भी टकरा रही है। वजह स्पष्ट है–पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव। वहां आम आदमी पार्टी का मुख्य मुकामला कांग्रेस से ही है। उसे लग रहा है कि इस मुद्दे पर अगर कांग्रेस ने बढ़त बना ली, तो उसे पंजाब चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी का आखिरी गढ़ पंजाब ही है, जिसे वह किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। दूसरी ओर, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ अपनी बॉन्डिंग को और मजबूत कर सकते हैं, जहां अगले साल की शुरुआत में बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का अच्छा प्रभाव है। वहां उनका एक मजबूत जनाधार भी है और उन्हें बड़े तबकों का समर्थन मिलता आया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने के दौरान अखिलेश यादव भी राहुल के साथ मौजूद थे और उन्होंने भी गिरफ्तारी दी। यह दोनों नेताओं के बीच बेहतर सियासी तालमेल का सबूत है, जिसे उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक बनाए रखना होगा। इसके अलावा, देशभर में दलितों या पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी सामाजिक संगठन हैं, राहुल गांधी उनका साथ ले सकते हैं। यह सामाजिक न्याय को लेकर राहुल की लड़ाई के अनुकूल भी रहेगा और राजनीतिक रूप से फायदेदां भी है।

हालांकि, इस पूरे माहौल में राहुल गांधी को अपनी चुनावी चालें बेहद सावधानी से चलनी होंगी। सबसे करीबी परीक्षा पंजाब में होने जा रही है। अगर कांग्रेस वहां चुनाव

हिंदुस्तान के हिस्से का बिल भी भर रहा है पाकिस्तान!

नीरज कुमार दुवे

सीमापार आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बना चुके पाकिस्तान की आज ऐसी दुर्गति हो चुकी है कि वह भारत के खिलाफ साजिश रचने की कीमत भी अपनी जेब से चुका रहा है। दरअसल, सिंधु जल संधि को लेकर भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घेरने की नाकाम कोशिश में इस्लामाबाद न केवल अपनी ओर से खर्च उठा रहा है, बल्कि भारत के हिस्से का व्यय भी खुद अदा कर रहा है। यानी जिस देश को वह कटघरे में खड़ा करना चाहता है, उसी का बिल भी उसे भरना पड़ रहा है। यह दृश्य पाकिस्तान की आर्थिक बूढ़हाली, कूटनीतिक बेबसी और बौखलाहट का सबसे बड़ा प्रमाण है। दुनिया के सामने भारत को घेरने निकला पाकिस्तान आज अपनी ही बनाई चाल में फंसकर उपहास का पात्र बन गया है। हम आपको बताना दें कि सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत छह नदियों के जल के बंटवारे का ढांचा तय किया गया था। दशकों तक भारत ने संधि का पूरी निष्ठा से पालन किया, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को संरक्षण देता रहा। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ संदेश दिया कि जब तक पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद का विश्वसनी और स्थायी रूप से परित्याग नहीं करता, तब तक सामान्य स्थिति की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी क्रम में भारत ने संधि से जुड़ी कार्यवाहियों में अपनी भागीदारी स्थगित कर दी। भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। नई दिल्ली का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियां 1960 जैसी नहीं हैंहीं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, ऊर्जा की आवश्यकता, नई

प्रौद्योगिकी और सबसे बड़कर पाकिस्तान प्रायोजित सीमापार आतंकवाद ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। ऐसे में संधि को समीक्षा और नए सिरे से विचार स्वाभाविक आवश्यकता है। इसके विपरीत पाकिस्तान हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस मध्यस्थता प्रक्रिया से वह भारत पर दबाव बनाना चाहता है, उसी का पूरा आर्थिक बोझ भी उसे स्वयं उठाना पड़ रहा है। यह उस कूटनीतिक दिवालियेपन का प्रतीक है जिसमें पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी दलीलों जीवित रखने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार दिखाई देता है। सच्चाई यह भी है कि सिंधु जल संधि से दशकों तक सबसे बड़ा लाभ पाकिस्तान को मिला। भारत, ऊपरी प्रवाह वाला देश होने के बावजूद, संधि की कठोर शर्तों का पालन करता रहा। अनेक विशेषज्ञ लंबे समय से यह प्रश्न उठाते रहे हैं कि यह व्यवस्था भारत के हितों में अनुरूप नहीं रही। इसके बावजूद भारत ने जिम्मेदार राष्ट्र का परित्याग दिया। लेकिन जब पड़ोसी देश आतंकवादियों को शरण दे, प्रशिक्षण दे और भारत के निर्दोष नागरिकों का रक्त बहाने वालों को संरक्षण प्रदान करे, तब केवल सद्भावना के आधार पर संबंध नहीं चल सकते। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शोर मचाने से वास्तविकता नहीं बदलती। आतंकवाद और बातचीत, आतंकवाद और सहयोग, आतंकवाद और विश्वास, ये तीनों एक साथ नहीं चल सकते। यदि इस्लामाबाद यह सोचता है कि वह एक ओर आतंकियों को पालता रहेगा और दूसरी ओर जल समझौतों तथा वैश्विक संस्थाओं की आड़ लेकर भारत पर दबाव बनाएगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है।

अतीत को भूलो और आगे बढ़ो

कुछ लोग सोचते हैं कि चुपचाप रहना अध्यात्म है। कुछ समझते हैं कि खुशी में रहना ही अध्यात्म है। अध्यात्म इन दोनों का तालमेल है, उसमें बाहर से आप चुप नजर आते हैं, भीतर खुश रहते हैं और भीतर चुप रहते हैं और बाहर से खुश नजर आते हैं!

हमारे जीवन में दो तरह के उत्सव होते हैं। एक जब हम धन्यवाद या आभार प्रकट करते हैं यह किसी ईश्वर के प्रति होता है। दूसरा होता है कि हम अतीत को भुलाकर जीवन में आगे ब 7ने का फैसला करते हैं और यह मानते हैं कि जीवन तो अनंत है तो फिर कहीं रुक जाने या बैठ जाने का क्या तुक है। किसी भी तरह जीवन में खुश रहने या खुशी मनाना अच्छा है।

वास्तविक उत्सव तो यही है कि बिना किसी आयोजन के भी आप प्रसन्ना रहते हैं। जब आपका उद्देश्य पवित्र होता है तो उत्सव अपने आप में पूर्ण हो जाता है। तब शरीर, मस्तिष्क और आत्मा आनंद पाती है।

अगर उत्सव आपको अपने आसपास से जोड़ता है, अगर यह आपको दुखद अतीत से मुक्त करता है और भविष्य की उम्मीद बंधाता है तब आप किसी भी अतीत के काम का बोझ नहीं महसूस करेंगे। उत्सव का ही एक तरीका है दूसरों की सेवा करना। यह बहुत ही पवित्र काम है। दूसरों की मदद करने में खुशी की तलाश कीजिए और तब आप निश्चित ही आनंद पाएंगे।

जब किसी भी खुशी में



श्री श्री रविशंकर

पवित्रता और प्रार्थना जुड़ जाती है तो उसमें गहराई और प्रतिष्ठा आ जाती है। तब वह मस्तिष्क के लिए केवल मनोरंजन और शरीर के लिए रोमांच नहीं रह जाता है बल्कि इनसे बढ़कर वह आत्मा के लिए जरूरी पोषण बन जाता है। किसी भी तरह की ईर्ष्या मन में रखकर खुशी की तलाश नहीं की जा सकती है बल्कि उसे तलाशने के लिए तो आपको उदारता से किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना होगा।

खुशी तो हमारे जीने का एक ढंग है और खुशी पाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। खुशी मिलती है आपके उत्साह और काम करने के ढंग से। जब आप दुखी रहते हैं तभी खुशी की सबसे ज्यादा

जरूरत होती है। तब आपको अतीत की दुखद घटनाओं से मुक्त होकर खुशी की तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। तब आपके पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ बांटिए और आप पाएंगे कि आपने खुशी तलाश ली है।

जीवन हमेशा बेहतर दिशा में आगे बढ़ता है। इस सफर में कहीं-कहीं खराब रास्ता भी मिल सकता है लेकिन उन रास्तों से होकर भी आप अंततः तो जीवन में खुशी ही पाते हैं। कठिनाइयों से आप गहराई पाते हैं और खुशी आपको विस्तार का मौका देती है। जो बुद्धिजीवी होते हैं वे अतीत को अपने भाग्य की तरह देखते हैं और भविष्य को चुनाव की आजादी के तौर पर। इसके साथ ही वे अपने वर्तमान में प्रसन्ना रहते हैं। जो दुख को पीट पर उठाए घूमते हैं वे अपने अतीत के बारे में

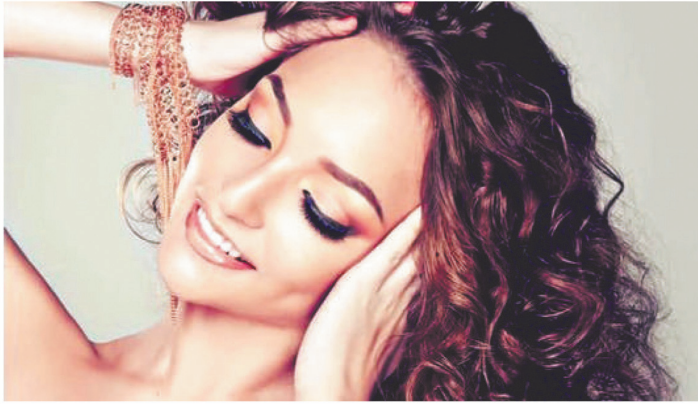
अक्सर शिकायती रवैया रखते हैं और भविष्य को अपने से दूर पाते हैं। ऐसे लोगों का वर्तमान भी दुखद हो जाता है। यह चुनाव आपके ही हाथ है। ऐसे सोचिए कि अतीत में जो हमारे साथ हुआ है उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसने बताया है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी भी दर्द से गुजरकर हमारे भीतर थोड़ी गहराई ही आती है और खुशी और आनंद हमें जीवन में नई चीजों को देखने और भविष्य के प्रति आशावान रहने का साहस देते हैं।

भविष्य का स्वागत मुस्कुराहट के साथ कीजिए। यह मुस्कुराहट तब आएगी जब आप इस तरह से सोचेंगे कि आपका भविष्य सुंदर ही होगा। अगर आप यह भरोसा नहीं करते हैं कि आगे सबकुछ ठीक होगा तो आप खुशी की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। तब आप असुरक्षा में ही जीते हैं। असुरक्षा के साथ ही लालच पैदा होता है। लालच के साथ स्वार्थ जुड़ जाता है। इसके पीछे-पीछे ही गुस्सा जीवन में आता है। गुस्से के साथ वासना की जगह बन जाती है। इसके पीछे उदासी और दुख जीवन में चले आते हैं। ये सभी एकदूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चुपचाप रहना अध्यात्म है। कुछ समझते हैं कि खुशी में रहना ही अध्यात्म है। अध्यात्म इन दोनों का तालमेल है, उसमें बाहर से आप चुप नजर आते हैं, भीतर खुश रहते हैं और भीतर चुप रहते हैं और बाहर से खुश नजर आते हैं। जब आप चुप रहकर खुशी व्यक्त करते हैं तो वह असली उत्सव होता है।

इस खुशी का असर भी ज्यादा होता है। यह एक रहस्य है। रहस्य समझने के लिए नहीं होते बल्कि उनसे प्रेम करना चाहिए। प्रेम भी एक रहस्य है, नींद रहस्य है, हमारा मस्तिष्क रहस्य है और हमारे इर्द-गिर्द जो कुछ भी है वह सबकुछ रहस्य ही है। इस रहस्य को जानने की कोशिश दुविधा है लेकिन इसके साथ जीना ही ज्ञान की प्राप्ति है।

कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं जानता तो कभी-कभी वे अज्ञानवश ऐसा कहते हैं। लेकिन जिन्हें ज्ञान हो जाता है वे भी कहते हैं, मैं मुझे पता जिसका अर्थ ही दूसरा होता है। इस तरह हर प्रश्न एक आश्चर्य में बदल जाता है। सरल और निर्दोष बनकर इस दूसरी अवस्था में रहो। उसे जिओ और तब आनंद अपने आप पैदा होगा।

कलीं बालों को ऐसे करें सीधा, अपनाएं ये टिप्स



घुंघराले बाल देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं। उतने ही इन्हें सुलझाना कठिन होता है।

» महिलाओं के ही नहीं पुरुषों के भी करली बाल होते हैं।

» लोग बालों को सीधा करने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। जब भी बालों को असर नहीं पड़ता।

» करली बालों में कई परेशानियां झलनी पड़ती है। आइए जानते हैं करली बालों को सीधा करने के नेचुरल तरीके...

2. एलोवेरा



एलोवेरा के गूदे को निकालकर इसमें तेल मिलाकर बालों में लगाने से आपको बाल चमकदार और सीधे हो जाएंगे।

3. मुल्तानी मिट्टी

» मुल्तानी मिट्टी, तेल और चावल का आटा मिलाकर लगाने से बाल सीधे होते हैं।

» इस पेस्ट को लगाने के बाद बालों को मोड़े नहीं।

4. अंडे का प्रयोग

» अंडे को फेंट कर इसमें ऑलिव ऑयल मिक्स कर लें। इस मिश्रण को बालों में लगाने के थोड़ी देर बाद बालों को शैम्पू कर लें। इससे बालों में चमक आती है और सीधे हो जाते हैं।



भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ते तनाव और ऐसे ही कई अन्य कैरणों के चलते सिरदर्द एक आम समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में लोग अक्सर पेन किलर का सहारा लेते हैं। लेकिन ज्यादा पेन किलर खाने पर रिएक्शन का डर बना रहता है। इसीलिए सिरदर्द दूर करने के लिए आप कुछ प्रभावी हर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि सिरदर्द के इलाज के लिए कौन से हर्ब्स मौजूद हैं।

पैशनफ्लॉवर

परंपरागत रूप से चिंता और अनिद्रा की स्थितियों के इलाज के लिए पैशनफ्लॉवर को जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह सिरदर्द के इलाज में भी कभी कारगर साबित होता है। जैसा की इसके नाम से पता चलता है यह हर्ब बड़ी इच्छाओं के चलते तनाव पूर्ण जीवन बिता रहे लोगों वाले लोगों के नर्वस सिस्टम को शांत कर सिरदर्द जैसी समस्या से बचाने में कारगर होता है।



वाइट विलो बार्क

अन्य सिरदर्द दूर करने वाली हर्ब्स की तरह वाइट विलो बार्क भी सिरदर्द दूर करने वाली एक कारगर हर्ब है। इस हर्ब को एस्पिरिन सॉलिमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक एनालजेसिक के रूप में यह हर्ब अन्य हर्ब्स की तरह लक्ष्णों को ना मिटाकर सीधा सिरदर्द को दूर करती है।



बटरबर और फीवरफ्यू

बटरबर और फीवरफ्यू के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि माइग्रेन और सिरदर्द दो अलग प्रकार की समस्याएं हैं। माइग्रेन सिर में रक्त के प्रवाह में तेजी से बदलाव के कारण होता है और गंभीर सिर दर्द , मतली, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, और ध्वनि के साथ जुड़ा हुआ होता है। जबकि सिरदर्द माइग्रेन का एक घटक है। बटरबर और



फीवरफ्यू दोनों ही बेहतर और नियमित रूप से सिरदर्द के इलाज के लिए उपयुक्त है।

ब्लेक कॉश

यह एक नेटिव उत्तरी अमेरिकी पौधा है। जिसका गठिया, सिरदर्द आदि के कारगर इलाज के लिए इस्तेमाल किये जाने का इतिहास रहा है। क्योंकि इस जड़ी बूटी में एस्ट्रोजन प्रभाव होता है, यह महिलाओं के लिए बेहतर है। लेकिन पुरुषों भी इसे कभी-कभी इस्तेमाल कर सकते हैं।



सरसों के बीज

सरसों सिरदर्द के उपचार में लाभदायक होता है। इसके लिए आधा चम्मच सरसों के बीज का पाउडर, 3 चम्मच पानी में घोलकर नाक पर लगाएं। इससे माइग्रेन और इससे होने वाले सिरदर्द म रोहत मिलता है।



अदरक

अदरक एक दर्द निवारक के रूप में भी काम करता है। यदि सिरदर्द हो तो सूखे अदरक को पानी के साथ पीसकर उसका पेस्ट बना लें और इसे अपने माथे पर लगा लें। इसे लगाने पर हल्की जलन जरूर होती है लेकिन यह सिरदर्द दूर करने में सहायक होता है।



दालचीनी

दालचीनी एक कमाल की हर्ब्स है, जो कई रोगों के उपचार में लाभदायक होती है। सिरदर्द के उपचार में दालचीनी को पानी के साथ महीन पीसकर कपाल पर पतला लेप करना चाहिए। लेप सुख जाए तो उसे हटाकर दोबारा नया लेप तैयार कर लगाना चाहिए।



पुष्कर मूल

पुष्कर मूल अर्थात पुष्कर की जड़ सिरदर्द की समस्या होने पर काफी सहायक हो सकती है। इसको चंदन की तरह घिसकर लेप को कपाल पर लगाने से सिर दर्द ठीक होता है। यदि आप घर में हैं और सिरदर्द की समस्या होती है तो इस लेप को लगा कर आराम करें। सिर दर्द जल्द ठीक हो जाएगा।



प्रिमरोज (पीतसेवती)

अगर आपके पास बहुत काम है, जिसकी वजह से आप अक्सर 12 घंटे तक दफ्तर में बिताते हैं, तो प्रिमरोज सॉलिमेंट्स को रेगुलर तौर पर लें। इसमें दर्द से आराम देने वाला कंपाउंड फिनायलानीन प्रवुर मात्रा में होता है। यही नहीं, प्रिमरोज कई अन्य बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है।



पिपरमिट

पिपरमिट माइग्रेन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। पुराने समय में सिरदर्द के लिए पिपरमिट ही दिया जाता था। इसलिए यदि आपको सिर दर्द की शिकायत होती है, तो आप इसे चाय में मिलाकर पी सकते हैं। इससे आपको तुरंत आराम मिलेगा।



कुछ अन्य हर्ब्स

अगर आप पिपरमिट, कैमामाइल और विलो बार्क को मिला कर चाय पीते हैं, तो आपको सिर दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। इसके अलावा लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, चेरी, लेवेंडर और सन पलौवर सीड्स आदि हर्ब्स भी सिरदर्द को ठीक करने में सहायक होती हैं।

मक्खन के चमत्कारी लाभ

मक्खन हर घर में पाया जाता है। मक्खन के बिना भारतीय नाश्ता अधूरा होता है। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब आप इनसे बच पाती हों। लेकिन कैलरी के लिहाज से कौन ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। यह जानना भी जरूरी है। इस बार जानिए मक्खन सेहत के लिए कितना बेहतर है। इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा मात्रा में मौजूद है। इसलिए यह छोटे बच्चों के बढ़ने के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिनको तिवर संबंधी समस्या होती है।



नया स्मार्टफोन लेने के बाद सबसे पहले करें ये 6 काम

यदि आप नया स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो आपको उसकी सिक्योरिटी के लिए भी जरूर कुछ करना चाहिए। इसके साथ ही आपके स्मार्टफोन में आपसे जुड़ी कई जानकारियां होती हैं, इसलिए आप जब भी कोई नया स्मार्टफोन लें, तो सबसे पहले ये 6 काम जरूर कर लें...

डिस्के की सुरक्षा से समझौता नहीं

अपने स्मार्टफोन की सुरक्षा के लिए उस पर अच्छी क्रॉलिटी का टेम्पर्ड ग्लास लगावाएं। सामान्य स्क्रीन गार्ड फोन की स्क्रीन को सिर्फ स्क्रीच आदि से बचाता है, लेकिन यदि आपने टेम्पर्ड ग्लास लगवाया है तो फोन गिरने पर भी यह उसकी स्क्रीन की सुरक्षा करता है।

बैक कवर का इस्तेमाल करें

अपने स्मार्टफोन की बाँड़ी को स्क्रीच, निशान और डेंट आदि से बचाने के लिए हमेशा अच्छी क्रॉलिटी का ही बैक कवर खरीदें। आप बैक कवर की मदद से अपने फोन को तरह-तरह के स्टाइलिश लुक्स भी दे सकते हैं, हालांकि आपकी प्राथमिकता फोन की सुरक्षा ही होनी चाहिए।

अपने स्मार्टफोन का बीमा कटाएँ

आजकल कई कंपनियां यूजर्स को स्मार्टफोन का बीमा कराने का ऑफर कर रही हैं। इसके अंतर्गत फिजिकल डैमेज, लिक्विड डैमेज और किसी मैकेनिकल खराबी के लिए भी बीमा कवर दिया जाता है। अगर कभी स्मार्टफोन में इस तरह की दिक्कतें आ जाएं तो इससे ग्राहकों को काफी फायदा होता है।

डाई फ्रुट्स

आजकल की लाइफ स्टाइल इस तरह हो चुकी है कि लोगों को अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रहता। उन्हें अपनी सेहत के हिसाब से क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज हम आपको सेहत से जुड़े कुछ खास डाई फ्रुट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनको खाने से आपको काफी फायदा होगा। यह दिमाग के लिए टॉनिक का काम भी करते है।

कहते हैं कि दरअसल, सूखे मेवों की तासीर गर्म होती है इसलिए इन्हें भिगोकर खाया जाना चाहिए। क्योंकि इसके छिलके की ऊपरी परत पर दूषित कण होते हैं। मेवों से बने उत्पाद खाने की बजाय इन्हें ऐसे ही खाना चाहिए और बहुत जरूरी है कि इनकी एक सीमित मात्रा का ही उपयोग किया जाए।

मेवों में उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है इसलिए ऐसे लोग जिन्हें किडनी रोग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या पाचन संबंधी रोग हो वे इन्हें डॉक्टर सलाह के बाद ही खाएं।

बादाम

कहते हैं बादाम में कैल्शियम,विटामिन ई, विटामिन की और फाइबर मौजूद होते हैं। जिससे ये सेहत के लिए जितने अच्छे हैं, उतना ही अधिक सेवन सेहत के लिए नुकसानदायी है। इसलिए दिन में 5 बादाम से ज्यादा न खाएं।



AppLock का इस्तेमाल करें

अपने निजी मेसेज, फोटो और दूसरे डेटा को दूसरों की नजर से बचाने के लिए आपको AppLock का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसे ऐंड्रॉयड फोन के लिए गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मदद से आप मोबाइल में मौजूद किसी भी ऐप, फोटो गैलरी आदि को लॉक कर सकते हैं।

फ़ोन के चोरी होने पर ये करें

स्मार्टफोन के चोरी होने या खोने पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इनसे बचने के लिए अपने ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन पर ऐंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर ऐक्टिवेट करें। इससे आप स्मार्टफोन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसके लिए Google Settings में जाकर स्कॉल डाउन करें और

Security ऑप्शन पर टैप करें। इसके बाद Android Device Manager पर जाकर Remotely locate this device और Allow remote lock and erase on or off को टिक कर दें। आपको Location की सेटिंग में जाकर Access to my location को भी ऑन करके रखना और फोन में गूगल साइन इन होना चाहिए।

ऐंटी-मैलवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल

आपके लिए स्मार्टफोन की स्क्रीन की सुरक्षा की तरह ही उसके डेटा की सुरक्षा करनी भी जरूरी है। नया फोन लेते ही सबसे पहले उसमें ऐंटी वायरस और डेटा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जिससे मोबाइल के महत्वपूर्ण डेटा और दूसरे सॉफ्टवेयरों की सुरक्षा को कोई खतरा न हो।

खाने से होते हैं ये फायदे, जानें किसमें कितना प्रोटीन



काजू

बादाम के बाद बात करते हैं काजू की। काजू को ड्राय फ्रूट्स का राजा भी कहा जाता है। काजू को प्रोटीन,आयरन, फाइबर और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। काजू का सेवन शरीर को ऊर्जा देने के साथ कई बीमारियों से हमारी रक्षा करता है।

किशमिश

यदि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है और आप भूलने लगते हैं तो किशमिश का सेवन बहुत बढ़िया है। इसे एक बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, जो स्ट्रेमिना बढ़ाता है। परंतु हमेशा इसका सेवन भिगोकर ही करना चाहिए।

सूखी अंजीर

मोटापा कम करने में कारगर अंजीर चाहे भूख को नियंत्रित रखने में सहायक होती है। लेकिन इसका अधिक सेवन जिगर के लिए हानिकारक हो सकता है। अंजीर बहुत गर्म होती है, इसलिए 5 दाने से ज्यादा न खाएं।

पिस्ता

पिस्ता हृदय रोगियों के लिए बेहद लाभकारी है, यह विटामिन बी-6 का प्रमुख स्रोत है। डाइटिंग कर रही महिलाओं के लिए पिस्ता फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय

प्रमुख समाचार

नए सीईओ तक पांच संतों को सौंपी जिम्मेदारी

लखनऊ। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना के बाद मंगलवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दूसरी बैठक हुई. बैठक के बाद ट्रस्ट ने बताया कि नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन फिलहाल नहीं हो पाया है. ट्रस्ट के अनुसार, नए सीईओ की नियुक्ति में करीब एक महीने का समय लग सकता है.तब तक मंदिर के संचालन और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी अयोध्या के पांच संत संभालेंगे. ट्रस्ट ने गोविंद गिरी की अध्यक्षता में एक धार्मिक समिति का गठन किया है, जो इस दौरान मंदिर के कार्यों की निगरानी करेगी. समिति में स्वामी रामानंद दास, महंत राजकुमार दास, स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ, स्वामी कमलनयन दास, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और स्वामी दिनेंद्रदास को सदस्य बनाया गया है.बैठक में कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और अहम फैसले लिए गए. बैठक में चढ़ावा चोरी मामले की विशेष जांच दल की जांच की समीक्षा की गई. ट्रस्ट ने चढ़ावा राशि की गणना में कथित अनियमितताओं से जुड़ी एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही।

शिक्षा के मुद्दे को सियासी हथियार न बनाएं

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक के आरोपों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों को अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का खुलकर समर्थन मिल रहा है. इस बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि बीते कई दिनों से लोग इस बात पर भी रिएक्शन दे रहे थे कि आखिर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान छात्रों पर हो रहे पुलिस के अत्याचार पर चुप क्यों है ? अब आखिरकार एक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़, लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है.सलमान खान ने लिखा, %यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था; बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया. जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदा है. पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है. मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका साथ दिया है.

दो मांगें पूरी, शंभू बॉर्डर से लौटे किसान

पंजाब। पंजाब के किसान मंगलवार को दिल्ली कूच के लिए शंभू, कुंडली और खनौरी बॉर्डर पर मंगलवार सुबह से जमा हुए थे. यह प्रदर्शन भारत और अमेरिका के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के खिलाफ किया गया और देश बचाओ मोर्चा ने इस समझौते को रद्द करने की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू किया था. हालांकि, किसानों की दो मांगें मान ली गई हैं. जिसके बाद शंभू बॉर्डर से किसान लौटने लगे. सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (चंदनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चंदनी को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जब वह दिल्ली में होने वाली किसान महापंचायत में जाने की तैयारी कर रहे थे. किसान जब सुबह-सुबह कूच करने लगे थे तो इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई थी।

सऊदी अरब और अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर डील

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच जिस मुद्दे को लेकर लंबे समय से तनाव और जंग हो रही है, उसी परमाणु संवर्धन (यूरेनियम एनरिचमेंट) को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है.

ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब के साथ ऐसे परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सऊदी अपनी जमीन पर नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन कर सकेगा. सूत्रों के मुताबिक, इस समझौते की औपचारिक घोषणा जल्द की जा सकती है. यह डील 30 साल के लिए होगी और इसमें अमेरिकी कंपनियां भी सऊदी के परमाणु कार्यक्रम के विकास में शामिल रहेंगे. अमेरिका और सऊदी की संयुक्त स्टडी के बाद देश में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट बनाने का रास्ता भी खुल सकता है. यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब और ईरान लंबे समय से क्षेत्रीय राइवल रहे हैं।

ललित मोदी की 16 साल बाद होगी घर वापसी

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीगके पहले चेयरमैन ललित मोदी को 2009 आईपीएल-साउथ अफ्रीका स्क्वैरूमामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है. के अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकांश निष्कर्षों और लगाए गए जुर्मानों को रद्द कर दिया है. फैसले के बाद ललित मोदी ने कहा कि 16

साल से जिस सच की बात वह लगातार करते रहे, अब उस पर अदालत की मुहर लग गई है. फैसले के बाद ललित मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा- मैं इस फैसले से बेहद खुश हूं. कल का दिन मेरे लिए शानदार रहा. पिछले 16 साल से मैं यह लड़ाई लड़ रहा था. मीडिया और सभी लोगों से मैं जो कुछ कहता रहा, आखिरकार वही सच साबित हुआ. मुझे खुशी है कि ट्रिब्यूनल ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया. उनका मकसद हमेशा आईपीएल का हित रहा. मेरी चिंता सिर्फ आईपीएल की भलाई को लेकर थी. मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं था. अब वह अध्याय खत्म हो चुका है और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं. भारत वापसी पर ललित मोदी ने कहा कि अब वह देश लौटने की तैयारी कर रहे हैं।

पेपर लीक विवाद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले-

दोषियों को जल्द सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी सरकार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने, मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों और अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक अहम कदम है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री की ओर से यह घोषणा तब की गई है, जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में छात्रों-युवाओं का प्रदर्शन जारी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रेक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह अहम कदम मौल का पत्थर साबित होगा।



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा, पेपर लीक मामलों में जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाए का प्रधानमंत्री मोदी का फैसला युवाओं को सशक्त बनाने के प्रति उनके मजबूत संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है।

राजनाथ सिंह ने कहा, यह निर्णायक कदम उन लोगों के खिलाफ तेजी से और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा, जो हमारे युवाओं की उम्मीदों और भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं।

पीएम मोदी के बाद किरेन रिजिजू

का विपक्ष पर हमला

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को विपक्ष से अपील की कि वे बिना किसी शर्त के नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा में शामिल हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के छात्रों से जुड़े इस मामले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा में बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार तुरंत चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है और उन्होंने सवाल किया कि बहस से पहले किसी शर्त की क्या जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी ने

नीट पर चर्चा की मांग की है। चर्चा पर कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शर्त रखी जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको नीयत ठीक नहीं है।

विपक्षी दलों से संसद को चलने देने की अपील करते हुए रिजिजू ने कहा कि पहले से कोई शर्त न रखें। नीट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों से बिना किसी पूर्व शर्त के चर्चा करने का आग्रह किया। रिजिजू ने सदन में कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शर्तें न रखें। आइए बिना किसी पूर्व शर्त के चर्चा करें। हम आज ही शुरुआत कर सकते हैं। हम आज ही चर्चा शुरू कर सकते हैं। इस विवाद पर केंद्र सरकार के रुख का जिक्र करते हुए रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही देश को भरोसा दिला चुके हैं कि पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्यसभा में रिजिजू का यह बयान लोकसभा में सरकार द्वारा औपचारिक रूप से यह दोहराए जाने के एक दिन बाद आया है कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री ने निचले सदन को बताया था कि सरकार शुरू से ही ऐसी चर्चा के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा था कि बहस किस नियम के तहत होगी, साथ ही इसकी तारीख और अवधि क्या होगी, यह तय करने के लिए सदन के नेताओं के बीच बातचीत जरूरी थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सार्थक चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि संसद को केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार-विमर्श करना चाहिए ताकि जनता को इस विवाद पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी मिल सके।

सैंसेक्स 364 अंक टूटा निफ्टी 23,870 पर बंद

नईदिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 364 अंक (0.47 प्रतिशत) गिरकर 76,391.39 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी 127 अंक (0.53 प्रतिशत) टूटकर 23,869.60 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 इंडेक्स में अदाणी एंटरप्राइजेज, नेस्ले इंडिया और श्रीराम फाइनंस के शेयर सबसे ज्यादा नुकसान में रहे। सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फेमिकल और निफ्टी ऑयल एंड गैस में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। वहीं, निफ्टी मीडिया और निफ्टी ऑटो ने अन्य सेक्टरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।

कॉमैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नई ब्रेजा देगी टटकर!

नईदिल्ली। भारत के तेजी से बढ़ते एसयूवी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बीच मारुति सुजुकी ने ब्रेजा की रणनीति में बदलाव किया है। कंपनी अब पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों और उपभोक्ताओं की बदलती पसंद को ध्यान में रखकर ब्रेजा को नई पहचान दे रही है। शुक्रवार को अपडेटेड मॉडल की लॉन्चिंग से पहले देश की सबसे बड़ी कार मैनुफैक्चरर ने कहा कि नई ब्रेजा को किसी एक तरह के ग्राहक के बजाय ज्यादा बड़े कस्टमर सेगमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी का यह कदम ऐसे समय आया है जब पिछले 18 महीनों में ब्रेजा खरीदने वाले ग्राहकों की प्रोफाइल में बड़ा बदलाव आया है। पहली बार कार खरीदने वालों की हिस्सेदारी 8% बढ़ी है। मारुति सुजुकी ने कहा, अब हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा भारत क्या चाहता है।

एनसीडीईएक्स के जरिए म्युचुअल फंड में हो सकेगा ट्रांज़ैक्शन

नईदिल्ली। देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) के माध्यम से म्युचुअल फंड्स के लिए ट्रांज़ैक्शन कर सकेंगे। NCDEX ने म्युचुअल फंड ट्रांज़ैक्शन प्लेटफॉर्म 'NCDEX निधि' की शुरुआत की है। यह प्लेटफॉर्म सुव्यवस्थित और तकनीक आधारित एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए म्युचुअल फंड योजनाओं में लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराएगा। NCDEX द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है NCDEX निधि म्युचुअल फंड ट्रांज़ैक्शन प्लेटफॉर्म अगले सप्ताह 29 जुलाई से शुरू किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म सुव्यवस्थित और तकनीक आधारित एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से म्युचुअल फंड योजनाओं में लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराएगा। यह पहल भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के म्युचुअल फंड से जुड़े मास्टर सर्कुलर के तहत की गई है।

पाकिस्तान में पेट्रोल 6.39 और डीजल 7.83 रुपए महंगा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 23 जुलाई से पेट्रोल 6.39 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल 7.83 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरों के बाद पेट्रोल की कीमत 327.12 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 375.04 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई है। सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले 21 जुलाई को सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की मामूली कटौती की थी।

स्टोल प्रमुख समाचार

रोमांचक मुकाबले में हारें पीवी सिंधु



नईदिल्ली। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने चाइना ओपन 2026 में शानदार जज्बा दिखाया, लेकिन रोमांच से भरे मुकाबले में जीत उनके हाथ से फिसल गई। गुरुवार को खेले गए दूसरे दौर के मुकाबले में सिंधु को वलेंट नंबर-4 और घरेलू खिलाड़ी चैन युफेई के खिलाफ 16-21, 22-20, 21-18 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 29 मिनट तक चले इस मैराथन मुकाबले में सिंधु चार बार जीत से सिर्फ एक अंक दूर थीं, लेकिन चैन युफेई ने दबाव के क्षणों में शानदार वापसी करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। यह हार सिंधु के लिए बेहद निराशाजनक रही, क्योंकि वह लंबे समय बाद किसी टॉप-5 खिलाड़ी के खिलाफ लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के करीब थीं।

यह मुकाबला पिछले हफ्ते हुए जापान ओपन के सेमीफाइनल का दोबारा मैच था, हालांकि उस समय चैन युफेई के चोट के कारण बीच में ही हट जाने से सिंधु को विजेता घोषित कर दिया गया था। चाइना ओपन में उतरते हुए चैन ने अपनी पुरानी रणनीतियों में सुधार किया और शुरुआत से ही सिंधु पर आक्रामक रुख अपनाया। इस वजह से भारतीय खिलाड़ी शुरुआत में कुछ दबाव में जरूर दिखाई दीं, लेकिन उन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए शानदार वापसी की और पहला गेम अपने नाम कर लिया। मुकाबले की शुरुआत में चैन युफेई ने तेज खेल दिखाते हुए 5-2 की बढ़त बना ली। सिंधु ने स्कोर बराबर करने की कोशिश की, लेकिन चीनी खिलाड़ी लगातार बढ़त बनाए रखने में सफल रही। ब्रेक तक चैन 11-6 से आगे थीं और ऐसा लग रहा था कि सिंधु के लिए वापसी मुश्किल होगी। लेकिन भारतीय स्टार ने अपने अनुभव और आक्रामक खेल का इस्तेमाल करते हुए शानदार पलटवार किया। सिंधु ने लंबी रैलियों में धैर्य दिखाया और अपने क्रॉस-ड्रॉप शॉट्स से चैन को परेशान किया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

चिराग पासवान

जब 2020 में कोविड-19 महामारी ने लोगों के जीवन और आजीविका पर बुरा असर डाला, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महसूस किया कि फिर से पूर्वस्थिति बहाल करने की प्रक्रिया केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे सबसे छोटे उत्पादकों और उद्यमों तक भी पहुंचना चाहिए, खासकर उन उद्यमों तक, जो भारत के गांवों और छोटे शहरों में कार्यरत हैं। इस उद्देश्य के साथ, उस साल, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत खाद्य अर्थव्यवस्था के उस हिस्से के साथ हुई, जो लंबे समय तक औपचारिक वित्त और संस्थागत समर्थन से बाहर रहा था-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, जो पहले ही उत्पादन व बिक्री कर रहे थे और कुछ लोगों को रोजगार

दे रहे थे लेकिन जिनके पास आगे बढ़ने के लिए आवश्यक पूंजी या मार्गदर्शन नहीं था। यह योजना उस विश्वास को प्रतिबिंबित करती है, जिसे प्रधानमंत्री लगातार मानते रहे हैं, कि भारत की वृद्धि इसके आधार से शुरू होनी चाहिए, यानी उन लोगों के बीच, जो अपने खुद के उद्यम शुरू करना चाहते हैं।

पी.एम.एफ.एम.ई. के त्रया से जुड़े घटक के तहत अब तक 2 लाख से अधिक मंजूरियां दी जा चुकी हैं। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पीछे वे उद्यमी हैं, जो औपचारिक त्रया-प्रणाली से जुड़े हैं और जिन्हें अपने उद्यम-निर्माण का असली मौका मिला है। इनमें सबसे पहले व्यक्ति जमनालाल पाटीदार थे, जिनका आवेदन पी.एम.एफ.एम.ई. के तहत सबसे पहले मंजूर किया गया था। 10वीं पास इस उद्यमी के पास खाद्य प्रसंस्करण का कोई अनुभव नहीं था लेकिन इन्होंने 10 लाख रुपए के



निवेश के साथ धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू की। इस योजना की मदद से उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन की सुविधा मिली, और उनका विचार एक कामयाब व्यवसाय में बदल गया, जो आज 5 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। उसकी कहानी एक सरल बात बताती है। उद्यमिता केवल अच्छे परिवार या अच्छे शिक्षा प्राप्त लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने विचार को क्रियान्वित करने के लिए वित्त, तकनीक और सहायता

प्राप्त कर सकता है। आम भारतीयों को उद्यम बनाने और दूसरों को रोजगार देने में सक्षम बनाकर, पी.एम.एफ.एम.ई. योजना प्रधानमंत्री के उस विजन को आगे बढ़ा रही है, जिसमें नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वाले में बदलने की बात कही गई है।

इस बदलाव में महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही है। त्रया से जुड़ी 2 लाख मंजूरियों में से लगभग 44 प्रतिशत का लाभ महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को मिला है, जबकि 4 लाख से अधिक स्वं-सहायता समूह के सदस्यों ने अपने व्यवसाय को मजबूत और उन्नत करने के लिए शुरुआती पूंजी प्राप्त की है। पूरी योजना से 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आर्जित हुआ है और लगभग 6 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

75,000 से अधिक इकाइयां उद्यम

पंजीकरण और एफ.एस.एस.ए.आई. व जी.एस.टी. के तहत अनुपालन के माध्यम से औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुकी हैं। कई महिलाओं के लिए इसका मतलब है, घर या समुदाय में अस्थाय किए जाने वाले हानर को ऐसे मान्यता प्राप्त उद्यमों में बदलना, जहां उन्हें वित्त, तकनीक और बड़े बाजारों तक पहुंच मिल सके। इनमें से प्रत्येक संख्या के पीछे एक बड़ा लाभ छिपा है। एक कामकाजी उद्यमी किसान की उपज खरीदता है, हर फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है और अधिक मूल्य बेच रहा है, जहां इसे बनाया जा। एक स्थानीय फसल ब्रांडेड उत्पाद बन जाती है। एक घरेलू कौशल स्थायी रोजगार बन जाता है। समय के साथ, एक जिले की पहचान उसके द्वारा बनाई गई चीजों से होने लगती है। व्यावहारिक तौर पर यही वोकल फॉर लोकल है, एक समय में एक उद्यम।

अमलीपदर की रथयात्रा आस्था और संस्कृति की अमूल्य धरोहर: मुख्यमंत्री साय

रायपुर। अमलीपदर की ऐतिहासिक रथयात्रा छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ सबको साथ लेकर चलने और लोककल्याण का संदेश देते हैं। महाप्रभु का आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर सदैव बना रहे, यही उनकी प्रार्थना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गरियाबंद जिले के अमलीपदर में आयोजित भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथयात्रा महापर्व को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
आज रथयात्रा महोत्सव में
शामिल हुए और भगवान
जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं
माता सुभद्रा की विधिवत पूजा-



अर्वना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, राजिम विधायक रोहित साहू, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजीव लोचन महाराज सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सायने कहा कि

राज्य सरकार विकास और जनकल्याण के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि
मुख्यमंत्री बिजली बिल

समाधान योजना की अंतिम तिथि, जो जून माह तक निर्धारित थी, उसे उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन माह बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ कम करने और

उन्हें राहत प्रदान करने के लिए संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे राशि अंतरित की जा रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चौबीसों घंटे कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है तथा वे स्वयं प्रतिदिन शिकायतों की समीक्षा करते हैं।

उन्होंने कहा कि अब तक 42 हजार से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है, जो सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री विधुदेव साय ने बाल्टीजोर नाले पर पुल निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुल बनने से क्षेत्र के लोगों को वर्षभर सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। स्थयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विधुदेव साय ने अपना काफिला रोककर सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थियों से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई, भविष्य की योजनाओं और विद्यालय की गतिविधियों के बारे में बातचीत की।



रायपुर। 'उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने 73 करोड़ से अधिक के कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन' 'उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने 73 करोड़ से अधिक के कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन' 'उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने 73 करोड़ से अधिक के कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन' 'उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने 73 करोड़ से अधिक के कार्यों का किया

उप मुख्यमंत्री तथा कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज कोरबा में सुनालिया नहर मार्ग स्थित बहुप्रतीक्षित मल्टी-लेवल पार्किंग का लोकार्पण तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर का भूमिपूजन किया।

उन्होंने नगर निगम द्वारा दादरखुर्द में आयोजित लोकार्पण, भूमिपूजन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होकर कोरबा जिले को 73 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 36 करोड़ 37 लाख 94 हजार रुपये की लागत के 12 विकास कार्यों का भूमिपूजन तथा 37 करोड़ 45 लाख 40 हजार रुपये की लागत के 7 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वाणिज्य एवं उद्योग श्री लखनलाल देवांगन, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कँवर, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत और नगर निगम के सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

सड़क सुरक्षा के लिए आईआईटी मद्रास के साथ ऐतिहासिक एमओयू



रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के सड़क सुरक्षा उन्मुक्तता केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में आज रायपुर में डेटा-आधारित हाइपरलोकल इंटरवेंशन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण तथा

सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप
थे।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन एवं आईआईटी मद्रास ब्यवस्था के बीच कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में वैज्ञानिक एवं डेटा-आधारित दृष्टिकोण से काम लाना है। कार्यशाला में अधिकारियों को

बताया गया कि सड़क दुर्घटना-
 डेटा का विश्लेषण कर ब्लैक-
 स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थल
 की पहचान की जाएगी।
 हाइपरलोकल सड़क सुरक्षा उपाय
 और कम लागत वाले
 अभियंत्रिकी हस्तक्षेप वा-
 जाएँ। 'संजय' प्लेटफॉर्म के
 माध्यम से ब्लैक स्पॉट की सम-
 पर पहचान कर साक्ष्य-आधारित
 निर्णय लिए जाएँगे। प्रथम चरण
 राज्य के सड़क दुर्घटना की दृष्टि
 से सर्वाधिक संवेदनशील 10 जिल-
 को चिन्हित किया गया है। इ-
 जिलों में जिला प्रशासन, पुलिस
 परिवहन, लोक निर्माण विभाग व
 अधिकारियों को चरणबद्ध
 प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आईजेकेवी के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल केंद्रीय मंत्रालय में सचिव नियुक्त

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय सह प्रौद्योगिकी पार्क योजना की स्वीयरींग सह प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग समिति का सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। इतिहास राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना का उद्देश्य देश में जैव



प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की जा रही है। इन पार्कों की स्थापना राज्यों के सहयोग से की जा रही है, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर गठित यह स्टीयरिंग सह प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग समिति विभिन्न राज्यों में प्रस्तावित बायोटेक पार्कों के परियोजना प्रतिवेदनों को मंजूरी देने के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगी। समिति जैव प्रौद्योगिकी पार्कों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करे हुए आवश्यक मार्गदर्शन और समन्वय का कार्य भी करेगी।

विद्युत उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला आयोजित

अधिकारों एवं शिकायत निवारण प्रक्रिया की दी गई जानकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सेवा मानकों तथा उपभोक्ता हितों से जुड़े प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, अंबिकापुर द्वारा जशपुर में विद्युत उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला कार्यालय कार्यपालन, अंबिकापुर (संचालन एवं संस्थापन), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जशपुर में संपन्न हुई।

कार्यशाला में घरेलू एवं गैर-घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, विद्युत सेवाओं के लिए निर्धारित सेवा मानकों तथा शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम



को संबोधित करते हुए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष श्री डी.के. सेनी ने बताया कि नए विद्युत कनेक्शन, निम्न दायरे (एलटी) कनेक्शन का कवर्जेशन मीटर संबंधी शिकायतों के निराकरण में प्रधानमंत्री सूर्यग्रह रु मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नेट मीटरिंग पर सब्सिडी तथा टैरिफ श्रेणी परिवर्तन जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं

उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने उपभोक्ताओं से किसी भी समस्या की स्थिति में निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया।

कार्यशाला में जशपुर विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री श्री सत्य प्रकाश कुमार एवं कार्यपालन यंत्री श्री विनोद पंडित सहित विभागीय अधिकारी एवं विद्युत उपभोक्ता उपस्थित रहे।

सेवा सेतु

जनता के द्वार, डिजिटल सरकार

आपकी ज़रूरत की सेवाएं
अब घर बैठे एक क्लिक में

प्रमुख सेवाएं

- ✓ जाति प्रमाण पत्र
- ✓ राशन कार्ड सेवाएं
- ✓ आय प्रमाण पत्र
- ✓ पेंशन योजनाएं
- ✓ निवास प्रमाण पत्र
- ✓ जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र
- ✓ विवाह प्रमाण पत्र
- ✓ व्यापार लाइसेंस

567
सेवाएँ

35 विभाग
एक मंच पर

16,900+
सेवा केंद्र

44 लाख+
आवेदन

संवाद-48530/154

डिजिटल सुशासन की नई पहचान
सेवाएं हुईं त्वरित, पारदर्शी और आसान

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

सेवा सेतु

जनता के द्वार, डिजिटल सरकार

sewasetu.cgstate.gov.in

अधिक
जानकारी हेतु
स्केन करें

जनहित में तकनीक, जनसेवा में नवाचार
sewasetu.cgstate.gov.in

92034 06400